वैशाख कृष्ण पक्ष- 8, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-09, अंक - 274 पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म।प्र।/4-474/2024-26

भोपाल

10 अप्रैल 2026 शुक्रवार

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

आज का मौसम

34.0 अधिकतम

18.4 न्यूनतम

Page-7

मोहन यादव के वादे, तंत्र की बेरूखी और भाजपा की दरकती जमीन

समाचार विश्लेषण

राजेश सिरोठिया

मुद्दा किसानों से गेहूं खरीदी का

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सूबे के चार संभागों इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुर में दस अप्रैल की बजाए नौ अप्रैल से गेहूं की खरीदी का जो फरमान जारी किया था, उसके तहत सरकारी तंत्र ने पहले दिन मात्र 45 केंद्रों पर 1616 क्विंटल, यानि 161 टन गेहूं की खरीदी का दावा किया है। पूरे प्रदेश में बनाए गए 3627 केंद्रों में पहले दिन इतनी कम मात्रा में खरीदी मुख्यमंत्री के वादों के प्रति सरकारी तंत्र की गंभीरता की पोल खोलने के लिए काफी है।

सरकार ने इस बार बीते साल के मुकाबले एक लाख टन ज्यादा यानि 78 लाख टन गेंहू खरीदी का लक्ष्य तय किया है। बीते दस सालों में इस बार गेंहूं की बंपर पैदावार हुई है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक एक करोड़ दस लाख टन से भी ज्यादा। मप्र सरकार ने पहले भी किसानों का एक करोड़ टन से ज्यादा गेहूं खरीदा है। इस बार केंद्र व्दारा घोषित मूल्य यानि 2585 रूपए के साथ 40 रूपए अतिरिक्त बोनस देकर 2625 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी का मंसूबा साधा गया है। सरकार के मुताबिक 19 लाख 54 हजार किसानों ने खरीदी केंद्रों के जरिए अपना गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया है। लेकिन सरकारी दावों पर ही यकीन करें तो अभी तक मात्र 97 हजार 474 किसानों ने

4 लाख 46 हजार 582 टन गेहूं बिक्री के स्लॉट बुक किए हैं। जमीनी तस्वीर कुछ अलग कहानी बयां कर रही हैं। खरीदी की प्रक्रिया में हुई भारी देरी के चलते कृषि मंडियों में हजारों किसान पहुंच चुके हैं। वे मजबूरी में व्यापारियों के हाथों न्यूनतम समर्थन मूल्य तो छोड़िए, औने पौने दामों पर अपना गेहूं बेचने को मजबूर हैं। लेकिन किसी मंत्री - अफसर ने मंडियों का औचक निरीक्षण करके जमीनी हकीकत समझने की जरूरत नहीं समझी।

ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है कि कहीं खरीदी की प्रक्रिया से जुड़े तंत्र ने मोहन यादव सरकार और उनके मंत्री गोविंद राजपूत को घेरने की कोई साजिश तो नहीं रची? यह भी कि दिन ब दिन बेकाबू हो रहे जमीनी हालात कहीं भाजपा की जमीन को कमजोर तो नहीं कर रहे?

यह हैं समस्या की जमीनी हकीकत...

1. किसानों को खरीदी केंद्रों पर जाने के लिए लंबे इंतजार के चलते भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 15 अप्रैल से शुरू हो रहे शादी के मुहुर्तों के चलते हजारों किसान कृषि मंडियों में गल्ला व्यापारियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। हार्वेस्टर वालों के लंबित भुगतान के तकादे भी झेल रहे हैं।
2. सहकारी समितियों के कर्जे का मामला भी है। इसके तहत हर साल 31 मार्च का तारीख तक ब्याजमुक्त कर्ज की सुविधा है। इसके बाद भारी ब्याज की शर्त है। ब्याज से बचने सस्ती दर पर गेहूं बेचा वह भी घाटे में और जो नहीं बेच सके उनका घाटा भी तय। चौंकाने वाली बात यह कि खरीदी की तारीख बढ़ाने के साथ सरकार ने किसानों के ब्याज मुक्त कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई।
3. सरकार ने पहली बार खरीदी के लिए किसानों का वर्गीकरण किया। छोटे, मंझौले और बड़े किसान। लेकिन इससे फायदा किसी को नहीं हुआ। वजह, गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग बड़ी चुनौती है। सर्वर का धीमे चलने और बार-बार ठप होने से सीधा असर पड़ रहा है। इस दफे मंत्रालय में बैठे अफसरों ने स्लॉट बुकिंग की शर्तों में इतने नए कायदे जोड़े हैं कि बुकिंग का वक्त बढ़ गया।
4. जिन खुशकिस्मत किसानों का स्लॉट बुक हुआ तो उन्हें आगे की तारीख मिली। यह हाल उन चार संभागों के किसानों का है जहां 9 अप्रैल से खरीदी शुरू हुई है। जहां 15 अप्रैल से खरीदी होना है, उन संभागों में किसानों के क्या हाल होंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।
5. खरीदी की लंबी चलती आशंका के चलते खरीदी करने वाली नोडल एजेंसियां यानि सहकारी समितियों पर हम्मालों के मेहनताने का बढ़ता बोझ। इसका असर सरकार पर ही पड़ेगा या समितियां कंगाल होंगी।
6. खरीदी के बाद माल की भराई लंबी खिंचने का बोझ वेयरहाऊस संचालकों पर भी होगा। बिजली की कटौती के चलते जिन जनरेटरों का सहारा लेना पड़ रहा है, उसका किराया और डीजल का खर्चा बढ़ेगा।
7. जब किसानों की बंपर फसल आई है तो खरीदी के लक्ष्य उत्पादन के मुकाबले कम रखने के पीछे की वजह क्या है? क्या भारत सरकार और राज्य सरकार के पास गेंहू की कीमत चुकाने के लिए राशि की किल्लत है? या फिर आला नौकरशाह प्रक्रियाओं और पारदर्शिता के नाम पर किसान हितों को गल्ला व्यापारियों के हाथों गिरवी रखने की जुगत में हैं?
8. रूस-यूक्रेन वार के वक्त विदेशों में गेहूं की आपूर्ति पर मंडराए संकट का लाभ बेशक किसानों और उससे ज्यादा गल्ला व्यापारियों को मिला, लेकिन इस बार ईरान जंग के चलते हालत बिल्कुल अलग है। गेंहू निर्यात की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। देशी बाजार में डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा है। किसानों को गेहूं का उचित मूल्य बाजार में मिलना मुश्किल। खरीदी केंद्रों पर आने वाले साधारण गेहूं की तो छोड़िए लोकमन जैसा गुणवत्ता वाला गेंहू बाजार में एमएसपी से नीचे बिक रहा है।
8. जल्द खराब होने वाली जूट की बोरियों की जगह सरकार फिर से प्लास्टिक के बैग यानि पीपी (पॉलीप्रोपेलिन) बैग्स में गेहूं जमा करना चाहती है। यह पीपी बैग्स रिफाइनरी में कच्चे तेल की रिफाइनिंग से बचे अपशिष्ट से बनते हैं। सरकार लाख दावा करे लेकिन यथार्थ के खुरदुरे धरातल की सच्चाई यही है कि पीपी बैग्स की खरीदी केंद्रों पर भारी कमी है। गेहूं की बोरियों में भरवाई में देर होगी। हम्माल बेकार बैठे रहेंगे। या तो इसका खामियाजा उनका मेहनताने पर होगा या मजदूरों पर लंबे पड़ाव के चलते ज्यादा खर्चे का बोझ बढ़ेगा।

राजस्थान-बेंगलुरु, समय : दोप. 7.30 बजे

न्यूज विंडो

नीतीश ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ

नईदिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज राज्यसभा से अपनी नई पारी शुरू की। उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में आज शपथ ली। इसके लिए समारोह का आयोजन किया गया। राज्यसभा में सारी तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से निकलकर राज्यसभा पहुंचे। 16 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे।

15 साल पुरानी बसों के परिवहन पर लगी रोक वैध

जबलपुर। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को उस संशोधित नियम को वैध माना है, जिसके तहत 15 साल की समय सीमा पूरी कर चुके व्यावसायिक वाहनों (विशेषकर बसों) के परिवहन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार को परिवहन नीति बनाने और जनता के हित में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है।

दो कारों की टक्कर में मासूम समेत छह की मौत

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक सड़क हादसा सामने आया। नाथिया नवागांव के पास दो कारों की आमने-सामने टक्कर में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हो गए। दोनों कारें तेज रफ्तार में थीं और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है।

आज का कार्टून

इस्लामाबाद में होनी है अमेरिका-ईरान की शांति वार्ता

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को कैंसर बताया कहा - इस देश को बनाने वाले नरक में जलेंगे

भड़के इजराइल की प्रतिक्रिया... मध्यस्थता करने वाले का ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी. एजेंसी

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता से पहले इजराइल और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इजराइल पर लेबनान में नरसंहार करने का आरोप लगाया। आसिफ ने कहा- इजराइल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, वहीं लेबनान में नरसंहार हो रहा है। इजराइल निर्दोषों को मार रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया वे नरक में जलें।

इजराइल के पीएम ऑफिस ने आसिफ के बयान को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान इजराइल को खत्म करने की मांग जैसा है। इसे स्वीकार नहीं किया जा

सकता, खासकर उस देश से जो खुद को शांति वार्ता का मध्यस्थ बता रहा हो। इजराइल की प्रतिक्रिया के बाद ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट हटा दी। दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सीजफायर को लेकर अहम बातचीत की उम्मीद है। इस बीच ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने कहा है कि लेबनान में हमले रोकने और ईरानी हवाई क्षेत्र का सम्मान करने जैसे अहम मुद्दों का सीजफायर के बाद भी उल्लंघन हुआ है।

आज पाक पहुंचेंगे जेडी वेंस

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शनिवार को इस्लामाबाद के आलीशान होटल सेरेना में होगी। इसके लिए अमेरिकी डेलिगेशन आज यानी शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि ईरानी डेलिगेशन पहले ही पहुंच चुका है। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस टीम का नेतृत्व करेंगे।

हिजबुल्ला से बात करेगा इजरायल

इस बीच इजराइल ने एक नया कदम उठाते हुए लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू की जाए। हालांकि अभी तय नहीं है कि हिजबुल्ला इस पहल पर राजी होगा या नहीं।

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ने दी बदले की धमकी

इस बीच ट्रंप ने दावा किया है कि वह ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत में समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को 'काफी दर्दनाक' परिणाम भुगतने होंगे। ईरान की तरफ से भी सख्त रुख सामने आया है। देश के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कहा कि उनके पिता की हत्या का बदला लिया जाएगा और होर्मुज पर नियंत्रण को नए स्तर पर ले जाया जाएगा। वैसे भी सीजफायर के बाद इजराइल का रूख ईरान के अनुकूल नहीं है।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा

प्रयागराज, एजेंसी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में तैनात जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उनके दिल्ली वाले घर में भारी मात्रा में जले हुए नोट मिलने के मामले में उनके खिलाफ आंतरिक जांच चल रही थी। साथ ही महाभियोग की भी चर्चा थी। इसी बीच उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया है। दिल्ली वाले घर में जले हुए कैश मिलने के बाद उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था। पांच अप्रैल 2025 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। न्यायिक कार्य से उनको फिलहाल अलग किया गया था। उनके खिलाफ महाभियोग लाने के मामले में कमेटी का गठन किया गया है। कई सांसदों ने संसद में जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए नोटिस दिया था। फिलहाल जस्टिस वर्मा के खिलाफ आतंरित जांच कमेटी जांच कर रही है।

घर में मिले थे भारी मात्रा में जले हुए नोट

बंगाल के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र महिलाओं को देंगे 3 हजार महीना

कोलकाता, एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे 'भरोसे का पत्र' नाम दिया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल कालरात्रि के बुरे सपने के समान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो पहले 6 महीने में बंगाल में यूसीसी लागू करेंगे। साथ ही राज्य

की महिलाओं को हर महीने 3 हजार मिलेंगे। बंगाल में गौ-तस्करी रोकेंगे। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में सातवां वेतनमान दिया जाएगा।

नर्सिंग आरक्षण मामले में एमपी हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ ने नर्सिंग आफिसर के पद 100 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित करने के मामले में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदेश में हो रही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर रखने के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता विनोद सनोदिया द्वारा दायर याचिका में दो अप्रैल, 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन और विभाग के भर्ती नियम में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक बताया है।

बोरवेल में फंसा दो साल का मासूम चट्टानें आने से रुकी खुदाई

उज्जैन, एजेंसी

बड़नगर के पास झालरिया गांव में दो साल का भागीरथ देवासी खुले बोरवेल में फंसा है। रेस्क्यू टीम को उसकी लोकेशन 75 फीट की गहराई पर मिली है। एसडीआरएफ के कमांडेंट संतोष जाट ने कहा- हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के हाथों में रेस्क्यू रोप की रिंग पहनाकर उसे बाहर निकाल लिया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जॉइंट टीम भागीरथ तक पहुंचने के लिए 5 पोकलेन मशीनों की मदद से समानांतर सुरंग भी बना रही है। 40 फीट खुदाई होने के बाद चट्टानें आने की वजह से काम रोक दिया गया है। चट्टानें तोड़ने के लिए रेस्क्यू टीम ने हैमर मशीन बुलाई है। 200 फीट गहरे बोरवेल में पानी भी है। भागीरथ गुरुवार शाम करीब साढ़े 7 बजे बोरवेल में गिरा था। भोपाल से पहुंची एनडीआरएफ की टीम, हरदा, इंदौर और उज्जैन की एसडीआरएफ के साथ जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है।

मैदानी अफसरों की तैनाती में जनता के प्रति संवेदनशीलता का पैमाना

भोपाल

दोपहर मेट्रो विश्लेषण

मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कड़ी मशक्कत के बाद आईएएस अफसरों के फेरबदल की जो लिस्ट जारी की है उससे कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं। देर से ही सही, लगता है सरकार ने जिलों में आम लोगों को हो रही व्यावहारिक दिक्कतों को समझने की कोशिश की है। इस लिस्ट के ज़रिए उन अफसरों से निजात पाने की गंभीर क़वायद की गई है जो जनता की तकलीफों को नजरअंदाज करते रहे हैं। जिलों में कलेक्टरों की तैनाती में राज्य प्रशासनिक सेवा से आए सिर्फ़ उन्हीं अफ़सरों को महत्व दिया गया है जिन्होंने अपनी मैदानी तैनाती के दौरान अच्छी छाप छोड़ी है। जिनका जनता के प्रति संवेदनशील नजरिया रहा है। भोपाल में प्रियंक मिश्रा, नर्मदापुरम में सोमेश मिश्रा, सागर में प्रतिभा पाल और लोक शिक्षण आयुक्त के बतौर अभिषेक सिंह की तैनाती सरकार के इस नजरिए की मिसाल दिखती है। इसी तरह धार में राजीव रंजन मीणा, सिवनी में नेहा मीणा, उमरिया में राखी सहाय, श्योपुर में शीला दाहिमा को नई जिम्मेदारी भी सोच समझकर दी गई है।

प्रियंक मिश्रा

कौशलेंद्र विक्रम सिंह

सोमेश मिश्रा

प्रियंक मिश्रा को राजधानी की कमान धार जैसे संवेदी जिले में उनकी दूरदर्शी सोच के इनाम के बतौर मिली है। उन्होंने धार भोजशाला के बरसों से चलते विवाद के बीच बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन और नमाज की अदायगी के काम को जिस तरह से अंजाम दिया, उसकी जमकर तारीफ हुई थी। अब भोपाल जैसे शहर के बड़े कैनवास पर अपनी प्रशासनिक क्षमता की धाक स्थापित करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। इसी तरह प्रतिभा पाल के पास उज्जैन, इंदौर की निगमायुक्त की जवाबदेही के साथ रीवा जैसे जिले की कमान सफलतापूर्वक संभालने का अनुभव है। सागर कलेक्टर के ओहदे से हटाए गए संदीप जीआर को श्रमायुक्त बनाने का फैसला जिले की जनता के लिए बड़ी राहत के बतौर आया है। उनकी नकारात्मक छवि तथा जनता और जन प्रतिनिधियों की अनदेखी से उपजे असंतोष की गूँज बुंदेलखंड से लेकर भोपाल तक थी। उम्मीद की जाना चाहिए कि प्रतिभा पाल सागर में अपनी छवि से शहर की फिजा को बदलने में कामयाब होंगी। नर्मदापुरम में सोनिया मीणा की जगह मंडला से आए सोमेश मिश्रा भी ज़्यादा कारगर साबित होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह लंबे समय तक लोक शिक्षण आयुक्त रहीं शिल्पा गुप्ता की विदाई उनके व्यवहार से परेशान होते शिक्षक समुदाय को राहत देगी। सुलझे अफसर के बतौर नए लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह के आने से अराजक हो चुके शिक्षा विभाग को नए सिरे से संवारने और संभालने के अवसर पैदा होंगे। श्रीकांत बनोठ को नर्मदापुरम की जिम्मेदारी रास आएगी लेकिन असली परीक्षा तो मुख्यमंत्री के सचिव के साथ संचालक नगर नियोजन बनाए गए कौशलेंद्र सिंह की है। प्रदेश के कमोबेश सभी बड़े शहरों में बरसों से लंबित मास्टर प्लान को लागू कराना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। खासतौर पर तब जबकि अधिकांश बड़े शहर नए मास्टर प्लान के इंतजार में बेतरतीब विकास का पर्याय बन चुके हैं। प्रशासनिक बदलावों की कड़ी में अगली बारी मंत्रालय सहित कई अहम् ओहदों पर विराजित बड़े अफसरों की है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और सूबे के मुख्य सचिव अनुराग जैन, कितने सामंजस्य के साथ आगे की कदमताल का पाते हैं।

शहर में हर तरफ फैली गंदगी

शहर के कई क्षेत्रों में इन दिनों गंदगी और कचरे का अंबार देखने को मिल रहा है। नगर निगम की अनदेखी के चलते सड़कों पर जगह-जगह कचरा फैला हुआ है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्डों में लोगों को बदबू और गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। सड़कों के किनारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें समय पर उठाया नहीं जा रहा। कई जगहों पर नालियां भी जाम हो चुकी हैं, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और स्थिति और भी भयावह हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। इसका असर न केवल व्यापार पर पड़ रहा है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है।

राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा 1400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

अंग्रेजों के जमाने के पशु अस्पतालों की जगह नए भवन बनाने की तैयारी

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

जर्जर भवन, दरकी हुई दीवार, बारिश में टपकती छत सहित अन्य दिक्कतें ग्रामीण क्षेत्र के पशु अस्पताल भवनों की पहचान है। कारण, कई अस्पताल भवन तो अंग्रेजों के जमाने के हैं। बाद में बने कुछ अस्पताल भी जर्जर हो गए। इनकी जगह अब नए अस्पताल भवन बनाने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को 1400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र से अलग-अलग बजट शीर्ष में अलग-अलग अंशदान मिलने की आशा है, पर सभी में औसत 80 प्रतिशत तक राशि केंद्र से मिलने का अनुमान है। शेष 20 प्रतिशत के करीब राज्य सरकार को मिलानी होगी। पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत भी शहरी क्षेत्र के अस्पताल भवन बनाए जा रहे हैं। इसमें किसी शासकीय निर्माण एजेंसी को विभाग की जमीन देकर उसके बदले में निर्माण कराया जाता है। एजेंसी कुछ हिस्से का व्यावसायिक उपयोग करने की शर्त पर निर्माण करती है। बता दें कि कृषि के बाद सर्वाधिक जमीन गोपालन और पशुपालन विभाग के पास है।

केंद्र से मिलेंगी 178 पशु एंबुलेंस, सैद्धांतिक सहमति मिली

प्रदेश के अधिकतर विकासखंडों में दो-दो पशु एंबुलेंस चलाई जाएंगी। इसके लिए केंद्र से 178 नई एंबुलेंस मिलने वाली हैं। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस वर्ष अंत तक नई एंबुलेंस चलाने की तैयारी है। केंद्र से इसके पहले भी 406 एंबुलेंस मिली थीं। प्रदेश में 313 ब्लॉक हैं, अभी कुछ ब्लॉक में दो और कुछ में एक एंबुलेंस चल रही हैं।

अलग-अलग टैग से होगी बेसहारा पशुओं की पहचान

पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने बताया कि पालतू और बेसहारा पशुओं की पहचान के लिए उन्हें अलग-अलग रंग का टैग लगाया जाएगा। इसके लिए भी केंद्र सरकार से राशि मिलेगी। टैग में कोड भी रहेगा, ताकि आसानी से उनकी पहचान की जा सके।

केवल पूजा नहीं, समाज को जोड़ने और संस्कारों का स्थान बनें मंदिर

मंदिर चलो अभियान के तहत सामूहिक आरती संपन्न

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

सनातन संस्कृति और सामाजिक एकता को सशक्त बनाने की दिशा में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं राजा किशन राम पार्वती बाई ट्रस्ट, नेवरी द्वारा संचालित मंदिर चलो अभियान एक जन-आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवारश्री चित्रगुप्तधाम मनकामेश्वर महादेव मंदिर, नेवरी (लाल घाटी) में भगवान श्री चित्रगुप्त जी सहित समस्त देवी-देवताओं की सामूहिक आरती भक्ति एवं उल्लास के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि आज की आरती एवं प्रसाद कनाडा के श्रद्धालु कुणाल जोहरी एवं डॉ. शुभी श्रीवास्तव, भोपाल द्वारा सह परिवार समर्पित किया गया। यह दृश्य इस बात का प्रमाण बना कि भारतीय संस्कृति की जड़ें अब विश्व पटल पर और अधिक सुदृढ़ हो रही हैं। अभियान के संयोजक सुनील श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और संस्कारों को जीवंत रखने का केंद्र है। उन्होंने विशेष रूप से युवा पीढ़ी से प्रतिदिन मंदिर जाकर अपनी संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष राम गोपाल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष महेंद्र श्रीवास्तव सहित सौरभ कुलश्रेष्ठ, राकेश वर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, अमोल सक्सेना, आनंद श्रीवास्तव, राशि सक्सेना, सरिता सक्सेना, दीपा शर्मा, अभय मीणा, सेनी दादा, शिवम श्रीवास्तव एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

बी.टेक छात्र पर जानलेवा हमला करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

राजधानी के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में सरेराह गुंडागर्दी और बी.टेक छात्र पर जानलेवा हमला करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में दो बी.टेक और एक एमसीए का छात्र शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई छुरी भी बरामद कर ली है।

पुरानी रंजिश में किया हमला–पुलिस के अनुसार, घटना 7 अप्रैल की रात की है। फरियादी दिव्यांश आर्या और अभिनव राय अपने साथियों के साथ जीत होम्स कॉलोनी के गेट के पास खड़े थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी सौरभ ठाकुर उर्फ गोल्डी, रितेश यादव और यश रघुवंशी वहां पहुंचे और गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने जान से मारने की नियत से धारदार छुरी से हमला कर दिया।

आशाराम बापू का साधकों ने मनाया जन्मोत्सव हवन, जप किया

संतनगर. दोपहर मेट्रो।

गांधीनगर संत श्री आशारामजी आश्रम में पूज्य बापूजी का 86वां जन्मोसत्व मनाया गया। आश्रम में पहुंचकर भक्तों ने सामूहिक हवन, जप व गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए संकल्प किया । इस अवसर पर सामूहिक पादूका यात्रा, कीर्तन व सत्संग का भी आयोजन किया गया। श्री योग वेदांत सेवा समिति भोपाल के तत्वावधान में भंडारे का भी आयोजन किया गया। समिति के मीडिया प्रभारी हरीश मेहर चंदानी ने बताया कि कई वर्ष पूर्व से पूज्य बापूजी की आज्ञा से उनका जन्म दिवस पूरे भारत मे उनके भक्त सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें गरीब, निराश्रित वर्ग की बृहद स्तर पर सेवाएं होती हैं। भोपाल में भी ट्रस्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में छाछ वितरण, शर्बत वितरण, साहित्य बांटा गया।

सिंधी देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुआ भारतीय संविधान

संतनगर। भारत सरकार ने भारतीय संविधान का सिंधी भाषा के देवनागरी लिपि में नया संस्करण प्रकाशित कराया है। इस संस्करण का विमोचन 10 अप्रैल को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा किया जाएगा। इसी अवसर पर सिंधी भाषा दिवस भी मनाया जाएगा। सिंधी देवनागरी लिपि में संविधान का अनुवाद सांसद शंकर लालवानी की पहल पर संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि इस कदम से देश और विदेश में रहने वाले करोड़ों सिंधी भाषी लोगों को अपनी मातृभाषा में संविधान पढ़ने और समझने का अवसर मिलेगा। विमोचन समारोह में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सांसद शंकर लालवानी भी उपस्थित रहेंगे।

गौ सेवा के लिए संत समाज आगे आया 11 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान

संतनगर। गंगा धाम दरबार ने गौ सेवा को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट की ओर से श्री राधाकृष्ण गौ सेवा संवर्धन सोसायटी को 11,000 की सहायता राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर संस्था के कोषाध्यक्ष महंत स्वामी स्वरूप दास जी महाराज (अजमेर) तथा गंगा धाम दरबार के महंत तुलसीदास जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने गौ सेवा से जुड़े कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया।

लघुकथा शोध केंद्र समिति की मुंबई शाखा का उद्घाटन

लघुकथा सृजन के पहले चिंतन और बाद में मंथन भी है जरूरी - डॉ. मिथिलेश

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

लघुकथा सृजन के पूर्व चिंतन और बाद में मंथन ज़रूरी है। अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच स्पेस होना आवश्यक है। यह बात वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. मिथिलेश अवस्थी ने कही। वे शोध केंद्र समिति भोपाल की मुंबई शाखा के उद्घाटन एवं विशेष लघुकथा गोष्ठी के ऑन- लाइन आयोजन की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। स्वागत वक्तव्य देते हुए लघुकथा शोध केंद्र मुंबई की अध्यक्ष श्रीमती अलका अग्रवाल सिगतिया ने कहा की यह केंद्र मराठी और हिंदी भाषा के बीच सेतु का कार्य करेगा । इस अवसर पर लघुकथा शोध केंद्र की निदेशक कांता रॉय ने मुंबई केंद्र के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात् मुंबई केंद्र की सचिव डॉ. ममता माली के संचालन में एक महत्वपूर्ण लघुकथा गोष्ठी हुई जिसमें निर्मोही फड़के ने लकीर, सेवासदन प्रसाद ने कनवेक्स, डॉ. देवीदास वामने ने खाली कक्षा, वर्षा रावत ने सड़क, समीरा पात्रावाला ने अँधेरी गली की रौशनी, शर्मीला चौहान ने चिंगारी, मंजू गुप्ता ने बुझा हुआ चूल्हा, वर्षा गर्ग ने रहिमन पानी राखिये रचना पढ़ी। आरती सिंह, एकता एवं सुनीता आमभोरे ने अपनी लघुकथाओं का वाचन किया। इस अवसर पर डॉ. हूबनाथ पाण्डेय, डॉ दिनेश शाकुल, डॉ. उज्जवला केलकर ने भी शुभकामनाएंनये केंद्र को देते हुए विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में लघुकथा केंद्र समिति भोपाल के सचिव घनश्याम मैथिल अमृत ने आभार प्रकट किया। आयोजन में देश विदेश के अनेक लघुकथा प्रेमी लेखक एवं पाठक उपस्थित थे।

कोलार में सफाई सत्याग्रह की चेतावनी कांग्रेस पहुंची जोन कार्यालय

भोपाल। कोलार क्षेत्र में बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम अधिकारियों को चेतावनी पत्र सौंपा है। कोलार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोन 18 और जोन 19 के अधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। कांग्रेस का आरोप है कि कोलार के विभिन्न वार्डों में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब हो गई है। गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मच्छरों की बढ़ती समस्या को देखते हुए दवाई छिड़काव और फॉगिंग की भी तत्काल आवश्यकता बताई गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि एक सप्ताह के भीतर सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, नियमित रूप से फॉगिंग मशीन चलाई जाए और घर-घर से कचरा उठाने वाली गाड़ियां दिन में दो बार संचालित की जाएं। राहुल सिंह राठौड़ ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता सफाई सत्याग्रह शुरू करेंगे। इसके तहत कार्यकर्ता खुद सड़कों पर उतरकर झाड़ू लगाएंगे और महापौर व भाजपा पार्षदों के खिलाफ विरोध दर्ज करेंगे। इस दौरान कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मेट्रो एंकर

ग्रास्प फाउंडेशन का दीप स्तंभ समारोह आयोजित

सम्मान का उद्देश्य व्यक्तित्व को मंच पर लाना : पागनीस

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

समाज को उत्कृष्ट कर्य के लिये सम्मान प्रेरित करते हैं। यह कहना है प्रवेश और शुल्क विनियमन समिति के अध्यक्ष डॉ. रविंद्र कान्हेरे का। वह ग्रास्प फाउंडेशन भोपाल के दीप स्तंभ समारोह में बोल रहे थे। हिन्दी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन के निदेशक डॉ. वीके महाडिक को जहां प्रदेश का गौरव सम्मान प्रदान किया गया। वहीं भोपाल मराठी समाज ने उनके योगदान के लिये मराठी गौरव सम्मान प्रदान किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज श्रीवास्तव भी मंचासीन थे। अपने उद्बोधन में डॉ. रविंद्र कान्हेरे ने कहा कि यह सम्मान उन लोगों के लिये है जो समाज के लिये उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने डॉ महाडिक के चिकित्सा शिक्षा और समाजसेवा

क्षेत्र में कार्य को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि, उसे सोच समर्पण और उस सेवा भावना का होता है जो समाज को आगे बढ़ती है। इस दौरान अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री श्रीवास्तव का कहना था कि यह सम्मान समाज के लिये एक प्रेरणा है और हमें आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर डॉ अभिजीत देशमुख सहित ग्रास्प फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक जोहरी और सचिव स्मिता पागनीस के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मैनिट के पूर्व छात्र-छात्राओं द्वारा गठित स्वयं सेवी समूह ग्रास्प की सचिव स्मिता पागनीस ने यहां बताया कि समारोह का उद्देश्य केवल सम्मान देना नहीं है बल्कि ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर लाना है, जिन्होंने अपने कार्य और समर्पण से समाज को बहुत अच्छा अनुभव हो। उनकी प्रेरणा से सेवा के अनेक दीप प्रज्वलित होते हैं और यही प्रेरणा आगे चलकर समाज को नई दिशा प्रदान करती है। प्रदेश में पहला निजी मेडिकल कॉलेज खोलने का श्रेय डॉ व्हीके महाडिक को जाता है। इसके साथ ही ग्राम विकास चेतना केंद्र की मदद से व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन भी इनके द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर हेल्थ रिसर्च के साथ मेडिकल कॉलेज की जीआईएस मैपिंग के लिये पर अनुसंधान योजना क्रियांवयन में अग्रणी भूमिका निभाई है।

जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान के साथ जोड़ा जय अनुसंधान, सीएम यादव बोले-

कृषि केवल आजीविका नहीं, हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था की है धुरी

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषि केवल आजीविका नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रही है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है और प्रदेश के समग्र विकास का आधार भी है। उन्होंने कहा कि आज कृषि एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, मृदा की घटती उर्वरता और बाजार की अस्थिरता जैसी चुनौतियां हमें नई सोच और नवाचार की ओर प्रेरित कर रही हैं।सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के कृषि क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाओं का विस्तार हुआ है, तकनीक को खेतों तक पहुंचाया गया है और नवाचार को जन-आंदोलन का रूप दिया गया है। ड्रोन दीदी जैसी पहल के माध्यम से महिलाएं भी आधुनिक कृषि तकनीक से जुड़ रही हैं, वहीं कृषि सखियों के माध्यम से जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है।

डॉ. यादव ने कहा कि कृषिः मूलं जीवनम्-का भाव हमारे समाज की जीवन-दृष्टि को व्यक्त करता है। कृषि धन्य है, पवित्र है और जीवन का मूल आधार है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश की थीम पर पूरे वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को भविष्य की कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना और कृषि को लाभकारी, स्थायी तथा तकनीक आधारित रोजगार सृजन मॉडल में परिवर्तित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है। एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत किसानों का संपूर्ण डेटा डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है और इस योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी रहा है। डिजिटल किसान डेटा इंटीग्रेशन से किसानों की जमीन, फसल और उत्पादन से जुड़ी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो रही है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।

नवाचार को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता

सीएम ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की भावना के अनुरूप जय जवान-जय किसान के साथ जय विज्ञान जोड़ा गया था और वर्तमान दौर में इसमें जय अनुसंधान को भी जोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती, कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन और बेहतर मार्केट लिंकेज के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में खेती में नवीन पद्धतियों और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। रसायन मुक्त खेती, जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि अवशेषों अर्थात पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन, मंडियों के आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादों को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कृषि को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कृषक परिवारों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिल सके और शहरी परिवारों को ग्रामीण संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्राप्त हो। साथ ही फूड प्रोसेसिंग और एग्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और प्रदेश के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

किसानों के हित में किये जा रहे कार्य

पीएम किसान सम्मान एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 84 लाख से अधिक किसानों के खातों में प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की सहायता ।
गेहूं उपार्जन पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस।
धान पर 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि।
मूंग-उड़द की एमएसपी पर खरीदी तथा उड़द पर 600 रुपये बोनस ।
आपदा प्रभावित 24 लाख से अधिक किसानों को 2106 करोड़ रुपये की राहत ।
पहली बार सोयाबीन का एमएसपी पर उपार्जन और भावांतर योजना में 1500 करोड़ रुपये का भुगतान।
सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया गयां।
किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण।
1.79 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा।
पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 32 लाख किसानों को सोलर पंप।
सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना से सोलर बिजली से आय का अवसर।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति किसानों को 5 एचपी तक मुफ्त बिजली।
5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन।
हर साल 10 लाख नए कनेक्शन देकर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था ।
कोदो और कुटकी का क्रमशः 2500 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल पर उपार्जन
1000 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस ।
कृषि से जुड़े उद्योग लगाने वालों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी।
इन इकाइयों में कार्य करने वालों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन।
तुअर दाल आयात पर मंडी टैक्स समाप्त ।

उद्योगपति बोले- युद्ध खत्म होने के बाद भी नॉर्मल होने में लगेगा डेढ़ साल

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध का असर: मप्र की फार्मा कंपनियों का 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अटका

इंदौर/भोपाल, दोपहर मेट्रो

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध का असर मध्य प्रदेश के फार्मा सेक्टर पर गहराता जा रहा है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव इस उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के चलते मध्य प्रदेश की फार्मा कंपनियों का करीब 1000 करोड़ रुपए का निर्यात अटक गया है। एमपी से हर महीने 20,000 से अधिक दवाइयों के कंटेनर दुनिया के 190 देशों में भेजे जाते हैं। वहीं, उद्योगपतियों का कहना है कि भले ही युद्धविराम हो गया हो, लेकिन स्थिति सामान्य होने में 6 महीने से लेकर डेढ़ साल तक का समय लग सकता है। भोपाल-इंदौर सहित प्रदेश की लगभग 100 फार्मा कंपनियों का निर्यात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परेश चावला का कहना है कि युद्धविराम के बाद उम्मीद है कि अगले दो से तीन महीनों में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगी। लेकिन इस युद्ध ने इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है।

इंदौर से 3 हजार करोड़ का होता है एक्सपोर्ट- इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सचिव अनिल कुमार सबरवाल ने बताया कि इंदौर से हर महीने करीब ढाई से तीन हजार करोड़ रुपए का निर्यात होता है। इसमें फार्मा, कन्फेक्शनरी, केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट शामिल है।फार्मा सेक्टर की बात करें तो मध्य प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री का 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके पीछे वेसल (जहाज) महंगे होना और कंटेनर की कमी प्रमुख कारण हैं।

ये तीन कारण, जिनसे एक्सपोर्ट अटका

मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में दवाइयां और रॉ मटेरियल गल्फ देशों, अफ्रीकी देशों, यूरोपीय देशों और अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। वर्तमान में निर्यात प्रभावित होने के पीछे तीन प्रमुख कारण सामने आए हैं...

आर्थिक रूप से कमजोर होना : भारत की फार्मा कंपनियों, खासकर मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री की अधिकांश दवाइयां आर्थिक रूप से कमजोर देशों में सप्लाई होती हैं। उद्योगपतियों के अनुसार, इन देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण वे समय पर भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। कई देशों में डॉलर की कमी भी देखने को मिल रही है, जिससे एक्सपोर्टर्स को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है।

इंश्योरेंस महंगा होना: उद्योगपति अनिल कुमार सबरवाल के अनुसार, पहले इंदौर से एक कंटेनर में 80 से 90 लाख रुपए तक का माल भेजा जाता था, जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम अधिकतम 24 हजार रुपए तक होता था, लेकिन वर्तमान में जोखिम बढ़ने के कारण इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम करीब 5 गुना तक बढ़ाकर लगभग 1 लाख रुपए कर दिया है। यह अतिरिक्त लागत उद्योगपतियों के लिए भारी पड़ रही है।

ब्लैंक सेलिंग की समस्या : इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वेसल (जहाज) की कमी फिलहाल सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जब शिपिंग कंपनियों को किसी रूट पर अधिक जोखिम या देरी की आशंका होती है, तो वे उस ट्रिप को रद्द कर देती हैं। लॉजिस्टिक्स की भाषा में इसे %ब्लैंक सेलिंग% कहा जाता है। वर्तमान में अधिकांश कंपनियां इसी रणनीति पर काम कर रही हैं, जिससे शिपमेंट प्रभावित हो रहा है।

190 देशों में जाती हैं भारत की दवाइयां

चावला ने आगे बताया कि भारत से करीब 180 से 190 देशों में दवाइयां निर्यात की जाती हैं। भारत को 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' भी कहा जाता है। अमेरिका तक भारत की जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है। अमेरिका से लेकर सोमालिया और कांगो जैसे छोटे देशों तक, कई देश पूरी तरह भारतीय दवाओं पर निर्भर हैं।युद्ध के कारण जिस तरह सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, उसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। प्रदेश के प्रमुख फार्मा उद्यमियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस युद्ध ने केवल तात्कालिक नुकसान ही नहीं पहुंचाया, बल्कि बाजार की संरचना को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, भारत का फार्मा एक्सपोर्ट करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है।

रॉ मटेरियल पर भी प्राइस कंट्रोल जरूरी

फार्मा इंडस्ट्री के उद्योगपतियों का कहना है कि इस समय रॉ मटेरियल की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। उनका मानना है कि जैसे सरकार दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखती है, वैसे ही दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल पर भी प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। वर्तमान में रॉ मटेरियल पर किसी प्रकार का मूल्य नियंत्रण नहीं है। उद्योगपतियों का यह भी कहना है कि सरकार को दवा निर्माण में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल की जमाखोरी पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो बाजार में दबा हुआ 25-30 प्रतिशत रॉ मटेरियल बाहर आ सकता है और जमाखोरी की समस्या कम हो सकती है। सरकार के ऐसे कदम से एक-दो महीने के भीतर रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे दवाओं को लेकर बनी मौजूदा समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।

अगले हफ्ते कांग्रेस जिलाध्यक्षों की अग्निपरीक्षा

15 अप्रैल से चार दिन तक हरीश चौधरी करेंगे परफॉरमेंस रिव्यू फेल मिलने पर एक्शन तय

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त 71 जिलाध्यक्षों की अगले हफ्ते अग्निपरीक्षा होने जा रही है। दो चरणों में उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। कमजोर प्रदर्शन वाले जिलाध्यक्षों पर कार्रवाई, यहां तक कि हटाने तक का फैसला लिया जा सकता है। एमपी कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले के मुताबिक, जिलाध्यक्षों का दो माह के अंतराल में पहले दो-दो बार रिव्यू हो चुका है। इस बार की समीक्षा अहम मानी जा रही है। दिल्ली से वामसी रेड्डी भी भोपाल आकर पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी 15 से 18 अप्रैल तक चार दिनों तक संभागवार समीक्षा करेंगे। पीसीसी में जिलाध्यक्षों को बुलाकर संगठन निर्माण, कामकाज, चुनौतियों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इतने समय में संगठन निर्माण में क्या काम किया है, किस तरह से संगठन का गठन हुआ है, क्या चुनौतियां हैं और आगे किस तरीके से काम करना है इन सब पर चर्चा होगी।

16 अप्रैल को शिवराज के घर के सामने धरना- 16 अप्रैल को कांग्रेस, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के सामने धरना देगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन में किसानों से जुड़े मुद्दे, खासकर गेहूं खरीदी में देरी और वादाखिलाफी को उठाया जाएगा।

17 अप्रैल को ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मेलन

17 अप्रैल को नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें उनकी जिम्मेदारियों के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने की रणनीति बताई जाएगी। साथ ही जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों का प्रशिक्षण भी होगा।

21 हजार पंचायत कमेटियां बन चुकीं

अगला सप्ताह कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस संगठन का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है। पार्टी के मुताबिक 23 हजार में से 21 हजार पंचायत कमेटियों का गठन हो चुका है। इन सब को लेकर कैसे आगे जाएं और ब्लॉक लेवल पर कैसे व क्या कार्यक्रम करें इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी।

सिंहस्थ 2028 को भव्य बनाने की रफ्तार तेज, संतों के साथ मैदान में उतरा प्रशासन

उज्जैन, दोपहर मेट्रो

आगामी सिंहस्थ महापर्व को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने साधु संतों के साथ विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। भ्रमण की शुरुआत शनि मंदिर से की गई। इसके बाद अधिकारियों और संतों ने नए घाटों के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन ने सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी संतों को दी।

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि सिंहस्थ से जुड़े सभी कार्य तेजी से किए जा रहे

हैं। उन्होंने कहा कि साधु संतों और गुरुजनों को स्थल पर ले जाकर निर्माण कार्यों की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। करीब 29 किलोमीटर लंबे नए घाटों का निर्माण तेजी से जारी है, जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव कम होगा। प्रशासन द्वारा शिप्रा नदी को शुद्ध और आचमन योग्य बनाने के लिए चल रही परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया जा रहा है।

संतों के सुझावों को दिया जा रहा महत्व

कलेक्टर ने कहा कि साधु संतों के सुझावों को विशेष महत्व दिया जा रहा है और उन्हें अमल में लाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान संतों ने विकलांगजन सुविधाएं, महिलाओं के लिए वस्त्र परिवर्तन कक्ष, टॉयलेट व्यवस्था और घाटों की सीढ़ियों पर फिसलन रोकने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रशासन ने इन सभी सुझावों को नोट कर आवश्यक सुधार करने का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान मौजूद वरिष्ठ संत डॉ रामेश्वर दास जी महाराज ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि घाटों का निर्माण बेहतर गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है और अब तक करीब 42 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने सीएम से की मुलाकात

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर खेल संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्रिकेटर क्रांति गौड़ को आगे भी इसी तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्रीको कु. गौड़ ने क्रिकेट बाल भेंट किए।

नवागत अफसरों से बोले मंत्री 3 साल में दिखे बदलाव का असर

भोपाल। भोपाल स्थित मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में जनपद पंचायतों के नवागत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और विकासखंड अधिकारियों के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री ने अधिकारियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि अगले तीन वर्षों में ऐसा कार्य करें, जिससे उन्हें खुद अपने काम पर संतोष महसूस हो। उन्होंने कहा कि आत्मसंतुष्टि इस बात का संकेत है कि अधिकारियों ने आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है।

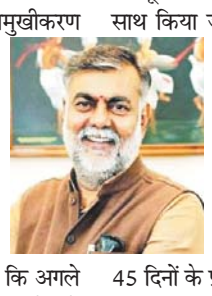

उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्यशैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि हर काम स्पष्ट योजना, मजबूत टीमवर्क और निरंतर प्रयास के साथ किया जाए, तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता के लिए संवाद को जरूरी बताया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने 45 दिनों के प्रशिक्षण में मिले अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने और फील्ड स्तर पर काम करने की व्यावहारिक जानकारी मिली, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके हैं।

दोपहर मेट्रो

प्रोपेगेंडा बहस पर बोले कलाकार संजय मेहता

युद्ध जैसी स्थितियां पूरी मानवता के लिए हैं खतरा

भोपाल, दोपहर मेट्रो

रंगमंच से फिल्मों तक अपनी पहचान बनाने वाले शहर के वरिष्ठ कलाकार संजय मेहता इन दिनों फिल्म धुरंधर: द रिवेंज को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म और समकालीन मुद्दों पर बातचीत के दौरान उन्होंने वैश्विक युद्ध, फिल्मों पर लगने वाले प्रोपेगेंडा के आरोप और सांस्कृतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर खुलकर अपनी राय रखी। मेहता ने कहा कि आज का दौर तकनीकी रूप से जितना विकसित है, उतना ही संवेदनशील भी है, ऐसे में युद्ध जैसी स्थितियां पूरी मानवता के लिए खतरा हैं।

फिल्मों पर लगने वाले प्रोपेगेंडा के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कई बार सच्चाई को भी प्रोपेगेंडा करार दे दिया जाता है। जब हम सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं तो लोग उसे प्रोपेगेंडा कह देते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं होतीं, लेकिन जब वे सामने आती हैं तो लोगों को लगता है कि यह किसी एजेंडे के तहत किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई मामलों में नए पहलू सामने आते हैं, जो पहले लोगों को पता नहीं होते। मेहता ने कहा कि कई बार ऐसी जानकारियां पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन वे आम जनता तक नहीं पहुंच पातीं। जांच एजेंसियों का काम हर चीज को सार्वजनिक करना नहीं होता, वे अदालत में केस पेश करती हैं। लेकिन मीडिया का काम है कि वह इन मुद्दों को सामने लाए। अगर कहीं यह नहीं हो पाता और कोई फिल्मकार उस जिम्मेदारी को निभाता है, तो उसे सीधे प्रोपेगेंडा कहना सही नहीं है।

युद्ध में जीत किसी की नहीं, हार इंसानियत की होती है

इन दिनों मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर संजय मेहता ने कहा कि किसी भी युद्ध में अंततः नुकसान इंसान का ही होता है। युद्ध कोई भी हो, उसमें मनुष्यता का नाश होता है। मरता इंसान ही है। बच्चे मरते हैं, युवा मरते हैं। हम आज चांद तक पहुंच गए हैं, एआई जैसी तकनीक हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें युद्ध की जरूरत पड़ रही है तो यह हमारे पूरे विकास पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद होने वाली तबाही को भरने में वर्षों लग जाते हैं और अगर कभी परमाणु युद्ध की स्थिति बनी तो उसके परिणामों की कल्पना भी संभव नहीं है। युद्ध की वजहों पर मेहता ने साफ कहा कि इसकी जड़ में अहंकार है। यह कहीं न कहीं अहंकार की लड़ाई है और अहंकार कभी जीतता नहीं है। वह हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।

कूल-ऑफ फैसलों में पारदर्शिता जरूरी

सांस्कृतिक संस्थाओं में चल रहे विवादों पर मेहता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर किसी संस्था या कलाकार को 'कूल-ऑफ' में डालना है, तो इसकी पहले से जानकारी दी जानी चाहिए और प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। उनके मुताबिक अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं, उनमें न पारदर्शिता है और न ही संवाद की गुंजाइश। उन्होंने कहा कि पहले इंटरव्यू होते थे, विशेषज्ञों की कमेटी बैठती थी और कलाकारों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता था, जिससे निर्णय संतुलित और स्पष्ट होते थे।

आधी आबादी को पूरा अधिकार

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या में महिलाओं की आबादी 48.5% थी। अनुमान है कि पिछले करीब डेढ़ दशक में इसमें कुछ सुधार ही हुआ होगा, लेकिन जो नहीं बदला, वह है देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) इसी स्थिति को बदलने वाला कानून है और इसके पास व लागू होने में देरी नहीं होनी चाहिए।

कमजोर प्रतिनिधित्वः आंकड़े बताते हैं कि राजनीति में महिलाएं महत्वपूर्ण तो रहीं, पर ज्यादातर वोट बैंक के नजरिये से। उनको उचित प्रतिधिनित्व आज भी नहीं मिल पाया है, जबकि हर क्षेत्र में समान अधिकार की बात की जाती है। मौजूदा लोकसभा में महज 14% महिला सांसद हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में तो स्थिति और खराब है - महज 10% महिला विधायक। और जब महिलाओं को मौका ही नहीं मिलेगा, तो यह सुधरेगा कैसे।

लंबा इंतजार: भारत ने अपनी आजादी के साथ ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोटिंग का अधिकार देकर दुनिया के सामने नजीर पेश की थी, पर इसके अगले चरण - राजनीति में उनकी बराबर भागीदारी में देश पीछे रह गया। साल 1996 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार में पहली बार महिला आरक्षण बिल लाया गया था और तब से तीन दशकों में चार असफल प्रयास हो चुके हैं। अब सरकार ने बिल पास करने के लिए 16 से 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है।

लोकतंत्र में संतुलन: पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल में एक चुनावी रैली में महिलाओं से विपक्षी दलों पर दबाव बनाने की अपील की, ताकि संसद में महिला आरक्षण बिल बिना किसी विरोध के पास हो सके। आदर्श स्थिति तो यह होगी कि बिल को हर दल का साथ मिले, दबाव बनाने और विरोध की नौबत ही न आए। देर से ही सही, कम से कम अब इस काम को अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए।

नीतियों पर असर: जब सदन में ज्यादा महिलाएं होंगी, तो आधी आबादी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा आवाज मिलेगी। उनकी समस्याओं पर ज्यादा सटीक और संवेदनशील चर्चा हो सकेगी, जिससे नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। महिलाओं की अनगिनत उपलब्धियों के बावजूद राजनीति उन कुछ क्षेत्रों में है, जहां उन्हें बराबर मौके नहीं मिल पाते। महिला आरक्षण बिल इस कमी को दूर करेगा। इस बदलाव का असर पूरे समाज पर पड़ेगा। महिला आरक्षण का सवाल सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं, भारत के लोकतंत्र को और संतुलित व न्यायपूर्ण बनाने का मुद्दा है।

एआई की दौड़ में अमेरिका-भारत साथ-साथ स्थायी और व्यावहारिक साझेदारियां

गिरिराज अग्रवाल
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिका नए और बेहतर एआई अनुसंधान में अग्रणी बना हुआ है, जबकि भारत बड़े स्तर पर एआई के कुशल और प्रतिभावान लोग प्रदान करता है। इसके साथ ही भारत में एआई तकनीकों के व्यापक वास्तविक प्रयोग की परिस्थितियां मौजूद हैं। विशेषज्ञ एआई अनुसंधान में अमेरिका-भारत सहयोग को मज़बूत करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराने और संस्थागत सहयोग को और अधिक समन्वित करने पर जोर देते हैं, जिससे कि अमेरिका-भारत एआई पहलों को सही दिशा दी जा सके। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो के कंप्यूटिंग, सूचना और डेटा विज्ञान स्कूल के विशिष्ट प्रोफेसर और डीन राजेश गुप्ता बताते हैं, 'वास्तव में, अमेरिका-भारत सहयोग एआई में बहुत उच्च स्तर पर है। मैं भारत में छह एआई स्कूलों के निर्माण में शामिल हूं, और अमेरिका की फाउंडेशन उन्हें मदद दे रही हैं।

इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर राजीव बरुआ कहते हैं कि सहयोग अधिक रणनीतिक और संस्थागत होता जा रहा है। उनके अनुसार, 'पूरकता स्पष्ट हैः अमेरिका अग्रिम अनुसंधान और वैश्विक उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई प्रदान करता है, जबकि भारत व्यापक स्तर पर उत्कृष्ट प्रतिभा और विविध वास्तविक-विश्व अनुप्रयोग संदर्भ प्रदान करता है।' सबसे बड़ा साझा अवसर विश्वसनीय, सुरक्षित और लागत-प्रभावी एआई सिस्टम बनाना है, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया जा सके। बरुआ के अनुसार एआई अनुसंधान में संस्थानों के बीच सहयोग को सक्षम बनाने के लिए साझा अनुसंधान इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, शिक्षा को एक प्रभावी गुणक के रूप में उपयोग करना, और शुरुआत से ही एआई सिद्धांतों जैसे सुरक्षा, संरक्षा और मजबूती को शामिल करना ज़रूरी है।

शैक्षणिक सेतु का निर्माण: शिक्षा और प्रतिभा विकास दीर्घकालिक सहयोग की नींव बने हुए हैं। डीन राजेश गुप्ता ऐतिहासिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर का उदहारण देते हैं। 'अमेरिकी सरकार ने आठ अमेरिकी विश्वविद्यालयों को साथ लाकर आईआईटी कानपुर के निर्माण में मदद की। उन विश्वविद्यालयों को शायद कभी पता भी नहीं था कि कानपुर कहां है, लेकिन उन्होंने संपर्क स्थापित किए।'

आज, भारत के उभरते एआई संस्थान साझेदारियों से लाभ उठा सकते हैं। 'आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी गुवाहाटी सहित कई भारतीय संस्थानों में अब एआई पर केंद्रित संस्थान हैं। इन संस्थानों को अमेरिकी साझेदारों से जोड़ना सहयोग को तेज कर सकता है।' वह जोड़ते हैं कि सहयोग अक्सर जमीनी स्तर से शुरू होता है। 'लोग सोचते हैं कि सहयोग के लिए बड़ा बजट या उच्च-स्तरीय समझौता चाहिए। लेकिन वास्तव में यह जमीनी स्तर से शुरू होता है। यदि हाई स्कूल और ग्रेजुएट स्तर के विद्यार्थी इन नए विषयों को सीखना शुरू करते हैं, तो वे भविष्य के लिए प्रतिभा स्रोत बन जाते हैं, जैसे आईआईटी बने।' प्रतिभा पाइपलाइन और सहयोग को मज़बूत करने के लिए डॉ. बरुआ व्यावहारिक उपायों पर जोर देते हैं। 'द्विपक्षीय कार्यक्रम जो द्वि-राष्ट्रीय टीमों का समर्थन करते हैं और वास्तविक दुनिया पर प्रभाव डालने पर जोर देते हैं, विशेष रूप से प्रभावी होते हैं,' वह समझाते हैं। 'सफल सहयोग में तीन विशेषताएं होती हैंः स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य, कोड, डेटा या बेंचमार्क जैसे साझा संसाधन, और सह-मार्गदर्शन, यात्राओं और नियमित कार्यशालाओं के माध्यम से निरंतर व्यक्तिगत संपर्क।' सफल साझेदारियां अमेरिका की बौद्धिक स्वतंत्रता की संस्कृति से भी लाभान्वित होती हैं, जहां व्यक्ति उम्र या डिग्री की परवाह किए बिना चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, जिससे सीमाओं के पार नवशोध को बढ़ावा मिलता है।

साझा अनुसंधान इंफ्रास्ट्रक्चर: दोनों विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि बातचीत से आगे बढ़कर साझा अनुसंधान प्लेटफार्मों की ओर बढ़ना आवश्यक है। डॉ. बरुआ बताते हैं, 'संवाद से आगे बढ़कर साझा सहयोग इंफ्रास्ट्रक्चर– एक जैसे समस्या विवरण, बेंचमार्क डेटासेट और दोहराई जा सकने वाली टेस्टिंग सुविधाएँ, ताकि परिणाम संस्थानों के बीच साझा हो सकें।' प्रभाव तब और तेज होता है जब राष्ट्रीय एजेंसियां स्वास्थ्य, कृषि और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में 'चैलेंज एजेंडा' निर्धारित करती हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एआई शोध समुदायों को मापनीय लाभ प्रदान करे और साथ ही उत्पादकता और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे। बरुआ कहते हैं, 'प्रयोगशाला से नागरिक लाभ तक का पुल उद्यमिता के माध्यम से बनता हैः अधिक संयुक्त पायलट परियोजनाएं, नवाचार प्रयोगशालाएं और कंपनियों को सह-विकास के लिए प्रोत्साहन।' मजबूत उद्योग भागीदारी डेटा, बाधाओं और कार्यान्वन के बारे में फीडबैक प्रदान करके वास्तविकता को बढ़ाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि परिणाम केवल शोध पत्रों तक सीमित न रहकर उत्पाद और सेवाओं में परिवर्तित हों।

डॉ. बरुआ आने वाले दशक में एआई नेतृत्व के लिए तीन आधार रेखाएं बताते हैंः साझा अनुसंधान इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्वसनीय एआई के लिए साझा मानक, और मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन। डॉ. गुप्ता जोड़ते हैं कि एआई तकनीक वर्तमान में परिपक्वता में दस में से तीन या चार के स्तर पर है और इसकी संभावनाएं अपार हैं। 'भविष्य उज्जवल है,' वह कहते हैं। 'सुविचारित नीतियों और सहयोग के साथ, आगे के अवसर अत्यंत व्यापक हैं।'

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

शक्ति प्रदर्शन, धमकियों और सैन्य गतिविधियों के बीच दबी मानवता की आवाज़

डॉ. सत्यवान सौरभ
स्तंभकार

दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, जहाँ शक्ति प्रदर्शन, धमकियों और सैन्य गतिविधियों के बीच मानवता की आवाज़ कहीं दब-सी जाती है। हालिया घटनाओं ने यह प्रश्न फिर से प्रासंगिक बना दिया है कि आखिर युद्ध से किसी को वास्तव में क्या मिलता है। क्या यह केवल ताकत का प्रदर्शन भर है, या इसके पीछे कोई स्थायी समाधान भी निहित होता है? इतिहास और अनुभव दोनों इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि युद्ध किसी समस्या का अंत नहीं करता, बल्कि वह नई समस्याओं की एक अंतहीन श्रृंखला को जन्म देता है। आज जब वैश्विक परिदृश्य में अस्थिरता बढ़ती जा रही है, तब यह प्रश्न और भी अधिक गंभीर हो उठता है।

युद्ध की शुरुआत प्रायः राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मरक्षा या सम्मान की रक्षा के नाम पर होती है, लेकिन इसका परिणाम कहीं अधिक व्यापक और विनाशकारी होता है। युद्ध के बाद जिन्हें विजेता कहा जाता है, वे भी भीतर से कमजोर हो जाते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है, संसाधनों की बर्बादी होती है, और सामाजिक ढांचा चरमराने लगता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे क्षेत्रों पर इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, पराजित देश तो पहले से ही विनाश के मलबे तले दब जाते हैं, जहाँ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया वर्षों तक चलती है और पीढ़ियाँ उसकी कीमत चुकाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक क्षति आम नागरिकों को उठानी पड़ती है, जिनका न तो युद्ध में कोई प्रत्यक्ष योगदान होता है और न ही निर्णय प्रक्रिया में कोई प्रभाव। युद्ध केवल भौतिक विनाश ही नहीं लाता, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरे घाव छोड़ता है। विस्थापन, भय, असुरक्षा और मानसिक आघात ऐसी स्थितियाँ हैं, जो युद्ध के बाद लंबे समय तक समाज को प्रभावित करती हैं। बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उनके जीवन की सामान्य धारा बाधित हो जाती है, और वे एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिए जाते हैं। सभ्यता, जो हजारों वर्षों में विकसित होती है, वह कुछ ही दिनों या महीनों में बिखर सकती है।

हाल के घटनाक्रम यह भी दर्शाते हैं कि बाहरी हमले और दबाव किसी देश को कमजोर करने के बजाय उसे और अधिक संगठित तथा आक्रामक बना सकते हैं। जब किसी राष्ट्र पर लगातार दबाव डाला जाता है, तो वहाँ राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाती है। लोग अपने आंतरिक मतभेद भुलाकर बाहरी खतरे के विरुद्ध एकजुट हो जाते हैं। इस प्रकार, जो रणनीति किसी देश को झुकाने के लिए अपनाई जाती है, वही उसे और अधिक सशक्त बना सकती है। यह युद्ध की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है कि वह अपने घोषित उद्देश्यों को भी कई बार पूरा नहीं कर पाता। युद्ध का प्रभाव केवल युद्धरत देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इससे सीधे प्रभावित होते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील समुद्री मार्गों पर उत्पन्न संकट पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएँ और निवेश में अनिश्चितता जैसे परिणाम वैश्विक स्तर पर दिखाई देते हैं। विकासशील देशों पर इसका प्रभाव और अधिक गंभीर होता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही सीमित संसाधनों पर निर्भर होती है।

जब महाशक्तियाँ किसी संघर्ष में शामिल होती हैं, तो स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। उनका हस्तक्षेप केवल सैन्य स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक आयाम भी ग्रहण कर लेता है। इससे छोटे और मध्यम देशों के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करना कठिन हो जाता है। वे अक्सर ऐसे संतुलन की तलाश में रहते हैं, जिसमें उनके राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें और वे किसी बड़े टकराव का हिस्सा भी न बनें। लेकिन यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि हर निर्णय के दूरगामी परिणाम होते हैं।

पश्चिम एशिया इस प्रकार के जटिल संघर्षों का एक प्रमुख उदाहरण है, जहाँ राजनीतिक, धार्मिक और सामरिक कारणों से तनाव लगातार बना रहता है। यहाँ की परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि एक छोटी-सी चिंगारी भी व्यापक संघर्ष का रूप ले सकती है। विभिन्न देशों और संगठनों की सक्रियता ने इस क्षेत्र को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। यहाँ होने वाले किसी भी घटनाक्रम का प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है।

आज की दुनिया को यह समझना होगा कि असली शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि सृजन में निहित है। जो देश और समाज इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, वही भविष्य में स्थायी शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। युद्ध के धुएँ में भले ही क्षणिक विजय का भ्रम दिखाई दे, लेकिन जब वह धुआँ छंटता है, तो पीछे केवल विनाश, पछतावा और अनिश्चितता ही शेष रह जाती है। यही युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई है–एक ऐसी सच्चाई, जिसे समझना और स्वीकार करना आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अपडेट

खराब लाइफ स्टाइल से जल्दी आता है बुढ़ापा, कुछ आदतों को पहचानकर छोड़ना अच्छा

एजिंग एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो लगातार होती रहती है। लेकिन हमारी रोज की आदतें इस प्रक्रिया पर काफी असर डालती हैं। कुछ अनहेल्दी काम या चॉइस एजिंग प्रोसेस की स्पीड तेज कर देते हैं। ठाणे स्थित जुपिटर हॉस्पिटल के डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, डॉ. अमित सराफ के मुताबिक, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से लेकर खराब स्लीप पैटर्न जैसी 7 डेली हैबिट शरीर में सेलुलर डैमेज, इंफ्लामेशन और क्रोनिक डिजीज का रिस्क बढ़ा देती हैं। हेल्दी एजिंग और लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए इन आदतों को पहचानकर बंद करना जरूरी है।

सेडेंट्री लाइफस्टाइल: फिजिकली इनएक्टिव रहना जल्दी बुढ़ापा महसूस होने का प्रमुख कारण है। डॉ. अमित सराफ का कहना है कि पर्याप्त शारीरिक गतिविधि ना करने से मसल्स मास कम होने लगता है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है और फैट बढ़ने लगता है। इसकी वजह से दिल की बीमारी, जोड़ों की समस्याएं और मेटाबॉलिक प्रोब्लम्स बढ़ती हैं। हर दिन 30 से 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करने का टारगेट रखें। एरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सही मिक्सचर फॉलो करने से मसल्स मास, बोन डेंसिटी और पूरी हेल्थ को सुधारने में मदद मिलती है।

खाने की अनहेल्दी चॉइस: प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर और अनहेल्दी फैट्स से भरी हुई डाइट लेने पर शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रोनिक इंफ्लामेशन बनती है। दोनों स्थितियों में सेल्स को डैमेज पहुंचता है, जिससे एजिंग तेज होती है। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरी बैलेंस्ड डाइट लें। खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फूड लें, जो कि सेलुलर डैमेज से बचाने में मदद करते हैं।

क्रोनिक स्ट्रेस: हमेशा तनाव में रहने से कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से शरीर का हर हिस्सा, हर अंग डैमेज होता है। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, खराब नींद, कमजोर इम्यूनिटी और मानसिक समस्याओं का खतरा बढ़ता है। डॉ. अमित सराफ के अनुसार, ज्यादा लंबे समय तक तनाव में रहने से बायोलॉजिकल एजिंग की स्पीड तेज होती है और हार्ट डिजीज का खतरा भी होता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, रेगुलर एक्सरसाइज और वॉकिंग व संगीत सुनने जैसे आसान तरीके अपनाएं, जो स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करते हैं।

स्मोकिंग और एल्कोहॉल : स्मोकिंग करने पर शरीर में खतरनाक टॉक्सिन घुसते हैं, जो खून की नलियों और ऑक्सीजन सप्लाई को बिगाड़ते हैं। इसकी वजह से शरीर के अंदर और बाहर की एजिंग तेज होती है। स्मोकिंग से लंग डिजीज, हार्ट डिजीज और कैंसर का खतरा होता है। वहीं, शराब का बहुत ज्यादा सेवन करने से लिवर हेल्थ खराब होती है।

सुविचार

कदर करना सीख लीजिए, ना जिंदगी वापस आती है, ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है।

-अज्ञात

निशाना

असर कुछ भी नहीं..!

दिनेश मालवीय 'अश्क'

बातें ही बातें किताबों की, असर कुछ भी नहीं
रात-दिन उस पर बहस, जिसकी ख़बर कुछ भी नहीं।
नाचता मस्ती मे अपनी है क़लंदर झूमकर
सामने उसके कोई फिर ताजवर कुछ भी नहीं।
चार पैसे पास जिसके, पूछते उसको सभी
खूबी-ए-ईमां की दुनिया में क़दर कुछ भी नहीं।
चल रहे बल पर गले के महफिलों में हर कहीं
जिनकी ग़ज़लों मे कहन, वज्नो-बहर कुछ भी नहीं।
आदमी ऊँचा उठे तो हाथ चूमें देवता भी
जो गिरे उसके बराबर जानवर कुछ भी नहीं।
'अश्क' जी को एक पल भी है नहीं फुरसत कभी
काम वैसे तो उन्हें आठों पहर कुछ भी नहीं।

कुछ अलग हो जाए

यहां चाव से पी जाती है भिंडी की कॉफी, अरबों का है बिजनेस, बीज को सुखाकर होती है तैयार

कॉफी की लत वाले लोग सुबह की पहली चुस्की के बिना दिन शुरू नहीं कर पाते। लेकिन कैफीन की वजह से कई लोग इसे कम करना चाहते हैं। ऐसे में दुनिया में एक अनोखा विकल्प लोकप्रिय हो रहा है। भिंडी की कॉफी या ओक्रा सीड कॉफी। जी हां, जिस भिंडी को हम सब्जी के रूप में खाते हैं, उसी के पके बीजों से एक स्वादिष्ट, नट्टी और पूरी तरह कैफीन-फ्री कॉफी बनाई जा सकती है। भिंडी की कॉफी बनाने की प्रक्रिया काफी सरल है। साथ ही इसका बिजनेस काफी प्रॉफिट देता है। इस कारण बीते कुछ समय से इस कॉफी का बिजनेस काफी बढ़ रहा है।

इस कॉफी को बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को पकने दिया जाता है ताकि उसके अंदर के बीज बड़े और सख्त हो जाएं। पकी हुई भिंडी को सुखाया जाता है, उसके बीज निकाले जाते हैं और अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सूखने दिया जाता है। सूखे बीजों को कड़ाही या ओवन में मध्यम आंच पर भूना जाता है। भुनते समय बीजों से कॉफी जैसी खुशबू आने लगती है और उनका रंग गहरा भूरा हो जाता है। भुनने के बाद ठंडा करके इन्हें पीस लिया जाता है। तैयार पाउडर को उबलते पानी में डालकर स्ट्रीप या फ्रेंच प्रेस में बनाया जाता है।

स्वाद लाजवाब: बात इसके स्वाद की करें तो भिंडी की कॉफी असली कॉफी जैसी नहीं होती, लेकिन इसमें नट्टी (hazelnut जैसा), टोस्टेड और अर्थी फ्लेवर आता है। यह हल्की और कम कड़वी होती है। कई लोग इसमें दूध, शक्कर या मसाले मिलाकर पीते हैं। कुछ इसे ओक्रा टी भी कहते हैं। यह कॉफी नई नहीं है, अमेरिकी गृहयुद्ध के समय जब असली कॉफी महंगी और दुर्लभ हो गई तो लोग ओक्रा सीड्स को भूनकर इस्तेमाल करने लगे थे। मैक्सिको, जाम्बिया और कई ग्रामीण इलाकों में आज भी इसे घरेलू स्तर पर बनाया जाता है। अब यह ट्रेंडिंग हो रहा है क्योंकि लोग हेल्दी और कैफीन-फ्री विकल्प की तलाश में हैं।

भिंडी की कॉफी के फायदे: 100% कैफीन-फ्रीः नींद की समस्या या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग आसानी से पी सकते हैं। पाचन के लिए अच्छीः भिंडी में फाइबर होता है, जो पेट को आराम देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूरः भिंडी के बीजों में स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं। भारत जैसे देश में भिंडी आसानी से उपलब्ध है, इसलिए यहां इसका चलन शुरू हो तो महंगी इंपोर्टेड डेकैफ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

नॉलेज

जादुई डेटा से पता चला समुद्र में कैसे जन्म लेती है सुनामी, बचाई जा सकेंगी लाखों जानें

वो शाम रूस के कामचटका प्रायद्वीप के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। समुद्र की गहराई में पृथ्वी की परतों के बीच दशकों से बन रहा दबाव अचानक रिलीज हुआ। इसका नतीजा था 8.8 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली भूकंप। इस भूकंप ने न सिर्फ जमीन को हिलाया, बल्कि पूरे प्रशांत महासागर के पानी को ऊपर की तरफ धकेल दिया। इससे एक ऐसी सुनामी पैदा हुई जिसकी लहरें 55 फीट (17 मीटर) से भी ज्यादा ऊंची थीं। अक्सर सुनामी की निगरानी के लिए समुद्र में लगे सेंसर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन समस्या यह है कि गहरे समुद्री ट्रेंच (खाइयों) के पास पर्याप्त सेंसर्स मौजूद नहीं होते। यहीं पर एंट्री होती है नासा और फ्रांस की स्पेस एजेंसी के 'सरफेस वॉटर एंड ओशन टोपोग्राफी' सैटेलाइट की। इस सैटेलाइट को असल में समुद्र के जलस्तर की रिसर्च के लिए बनाया गया था। लेकिन कामचटका की घटना के दौरान इसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर इग्नासियो सेपुलवेडा और उनकी टीम ने इस सैटेलाइट की मदद से सुनामी की 'पैदाइश' को लाइव देखा है।

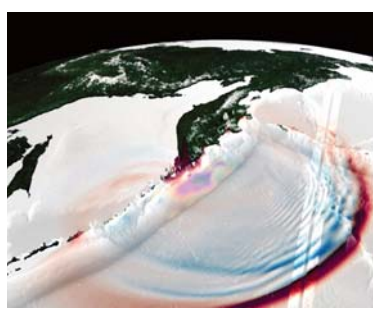

आमतौर पर सुनामी की निगरानी के लिए डार्ट (DART) बुआए का इस्तेमाल होता है, जो समुद्र की सतह पर लगे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट की जानकारी देते हैं, जिससे सुनामी के पूरे स्ट्रक्चर को समझना नामुमकिन होता है। इसके उलट SWOT सैटेलाइट ने 2D इमेजिंग के जरिए पूरे समुद्र की सतह का नक्शा ही खींच दिया। इससे वैज्ञानिकों को पहली बार पता चला कि लहरें किस दिशा में मुड़ रही हैं और उनकी बनावट कैसी है। नई रिसर्च से साबित हुआ कि ये छोटी लहरें ही असल में भूकंप के केंद्र और उसकी गहराई की सटीक जानकारी देती हैं। अब वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में कितनी हलचल हुई और उसका असर कितना भयानक होगा।

बचाई जा सकेंगी लाखों जानें: इस स्टडी का सबसे बड़ा फायदा सुनामी की भविष्यवाणी करने वाले सिस्टम को मिलेगा. जब वैज्ञानिकों के पास 2D डेटा और सटीक मॉडल होंगे, तो वे लहरों की ऊंचाई और उनके तट पर पहुंचने के समय का बिल्कुल सही अंदाजा लगा सकेंगे। इससे तटीय इलाकों को खाली कराने के लिए ज्यादा वक्त मिल पाएगा। डेनमार्क की टेक्निकल यूनिवर्सिटी और स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के एक्सपर्ट्स भी इस मिशन में शामिल हैं। यह साझा प्रयास दुनिया भर के तटीय देशों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।

न्यूज विंडो

युवक की हत्या, परिवार वालों ने शव रखकर इंदौर-बैतूल हाईवे पर लगाया जाम

खातेगांव (देवास)। अंचल के खातेगांव थाना क्षेत्र में इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे फोरलेन बायपास पर दाना बाबा धार्मिक स्थल के सामने संदिग्ध अवस्था में गुरुवार को मिले शव के मामले में आक्रोशित परिजनों ने शुक्रवार सुबह हाईवे पर थाने के सामने शव रखकर रास्ता जाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने रात में करीब चार संदिग्धों को पकड़ा था, सुबह जब परिजनों को पता चला कि इनमें से दो को ही मुख्य आरोपित बनाया जा रहा है तो उन्होंने थाने के सामने शव रखा और प्रदर्शन शुरू कर दिया।

सभी आरोपितों पर एकसमान कार्रवाई, मकानों पर बुलडोजर चलाने, फांसी दिलाने की मांग की गई। रास्ता जाम होने के बाद टीआइ विजय लोधी, एसडीओपी कन्नौद आदित्य तिवारी, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र शर्मा आदि मौके पर पहुंचे और उचित व नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया लेकिन स्वजन नहीं माने और सुबह करीब साढ़े नौ बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन साढ़े ग्यारह बजे तक भी जारी था। इसके चलते हाईवे पर आवागमन प्रभावित रहा, छोटे वाहन रास्ते बदलकर निकले।

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: लेडी सब इंजीनियर 10,000 रिश्वत लेते पकड़ाई

शहडोल। प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला शहडोल जिले का है जहां लोकायुक्त रीवा की टीम ने गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 को नगर परिषद कार्यालय खंड देवलौंद में पदस्थ लेडी सब इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। मेसर्स जेके अग्रवाल के संयोजक जेके अग्रवाल ने 7 अप्रैल 2026 को रीवा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे सुधा वर्मा, उम्र 35 वर्ष, पद उपयंत्री (सब इंजीनियर), नगर परिषद खंड बाणसागर, जिला शहडोल ने 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की है। अपनी शिकायत में फरियादी जेके अग्रवाल ने ये भी बताया कि उन्हें नगर परिषद खांड, शहडोल के खेल मैदान में स्टेयर निर्माण का कार्य न्यूनतम निविदा दर पर प्राप्त हुआ था। कार्य पूरा होने के बाद, अंतिम देयक तैयार किए जाने के लिए उपयंत्री सुधा वर्मा द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा रहा था और वह इसके लिए 20,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रही हैं। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को फरियादी जेके अग्रवाल को रिश्वत के 10 हजार रुपये देने के लिए उपयंत्री (सब इंजीनियर) सुधा वर्मा के पास भेजा। रिश्वतखोर सुधा वर्मा ने जैसे ही रिश्वत के पैसे लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम के सदस्यों ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 (क) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। टीम द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। इससे पहले बुधवार को नरसिंहपुर में जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने नगर पालिका के बाबू संजय तिवारी को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

आयोजन स्थल को लेकर अहिरवार समाज संघ ने प्रशासन के से की मांग

नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के आयोजन स्थल को लेकर अहिरवार समाज संघ ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी है। समाज के प्रतिनिधियों ने जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र नागेश को कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर कार्यक्रम प्रतिमा स्थल पर ही कराने का आग्रह किया।अहिरवार समाज संघ के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी ने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुयायी चाहते हैं कि शासन द्वारा आयोजित होने वाला मुख्य कार्यक्रम शहर के डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क स्थित प्रतिमा स्थल पर ही हो। समाज का मानना है कि यह स्थान सार्वजनिक है और बाबा साहब की स्मृतियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

बालाघाट के लालबर्रा के बहेगांव में तालाब में डूबने से दो बच्चियों की मौत

बालाघाट। बालाघाट के लालबर्रा थाना क्षेत्र के बहेगांव में तालाब में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। दरअसल, प्रतिभा यादव और प्रिंसी यादव खेलते हुए तालाब के पास पहुंचीं और गहरे पानी में गिर गईं। उनके साथ मौजूद चार साल की जान्हवी ने परिजनों को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन तुरंत तालाब पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों बच्चियां गहरे पानी में डूब चुकी थीं। पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को बरामद कर पंचनामा कार्यवाही पूरी की और पीएम के लिए लालबर्रा अस्पताल भिजवाया। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री सड़क निर्माण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

डिंडौरी। डिंडौरी में जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे कुटेली दादर गांव के ग्रामीणों ने चार घंटे तक जाम कर दिया। ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अधिकारियों ने जल्द सड़क निर्माण शुरू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोला।

कामतोन कासिया में विकास कार्यों के नाम पर मची अंधेरगर्दी

भ्रष्टाचार का खेला... सीईओ ने दिए जांच के निर्देश, रडार पर सहायक सचिव

अमित श्रीवास्तव। औबेदुल्लागंज

ग्राम पंचायत कामतोन कासिया में विकास कार्यों के नाम पर मचे अंधेरगर्दी के खेल पर आखिरकार प्रशासन का डंडा चल गया है। जनपद पंचायत ष्टश्वह्ल निखिलेश कटारे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत इंस्पेक्टर को जाँच के निर्देश दिए हैं।

खबर है कि पंचायत में पूर्णकालिक सचिव की मौजूदगी के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर सहायक सचिव को वित्तीय प्रभार सौंपा गया। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि इसी अघोषित छूट की आड़ में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी बजट के साथ खिलवाड़ किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, यदि पंचायत के 10 वर्षों की निष्पक्ष ऑडिट हुई, तो पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा चिट्ठा खुलना तय है। प्रशासनिक सख्ती के बाद पंचायत के जिम्मेदार गलियारों में खलबली मच गई है। सवाल यह है कि क्या यह जांच सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाएगी, या जनता के टैक्स की पाई-पाई का हिसाब लेकर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। प्रशासन की साख अब पंचायत इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि साहब किसे बचाते हैं और किसे फँसाते हैं। इंस्पेक्टर कैलाश मेहरा ने बताया कि समाचार पत्रों की खबरों को संज्ञान में लेते हुए जनपद सी ई ओ औबेदुल्लागंज ने मुझे जांच करने के निर्देश दिए हैं। जल्द जाँच कर स्थिति जल्द स्पष्ट हो जाएगी।

गेहूं खरीदी जल्द शुरू करने की मांग

धार। दोपहर मेट्रो

जिले में गेहूं की फसल कटकर तैयार है, लेकिन सरकारी खरीदी शुरू न होने से किसान परेशान हो रहे है, बिचौलियों के हाथों किसान लूटा जा रहा है, उक्त बातें युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष रोहित कामदार ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कृषि उपज मंडी में कही, ज्ञापन में मांग की गई कि गेहूं की खरीदी तत्काल शुरु की जाए और किसानों को गेहूं की फसल का भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल के रुप में दिया जाए। ज्ञापन में युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी स्तर पर खरीदी में हो रही देरी का सीधा फायदा बिचौलिये उठा रहे हैं। किसान अपनी उपज को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। रोहित कामदार ने कहा,भाजपा सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। एक तरफ फसल तैयार है और दूसरी तरफ मंडियों में व्यवस्थाएं ठप हैं। यदि जल्द ही 2700 का दाम और खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। ज्ञापन में युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांग की है कि प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीदी तत्काल प्रभाव से शुरू की जाए, किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 प्रति क्विंटल प्रदान किया जाए अनाज मंडियों में पारदर्शी व्यवस्था हो ताकि किसानों को असुविधा न हो। ज्ञापन के दौरान हरदेव सिंह जाट, पंकज लोधा, आशीष भाकर, राजेश पटेल, लियाकत अली पटेल, धर्मेंद्र राठौर, सुरेश भैया परमार, राम पटेल (धार ब्लॉक अध्यक्ष), शकील खान, दिनेश बघेल, सरफराज, बंटी डोड, अर्पित बाबा, सोहेल निसार, मनोज चौहान, धर्मेंद्र भदौरिया, शुभम सोलंकी, मनीष कन्नौज, अभिनव बिंजवा, भेरू चौहान, जे.डी., मूफ्फु सैफी, जीतू बाबा, अजय ठाकुर और सिद्धार्थ भूरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अब हो रहे खुलासे

मोस्ट वांटेड चोर पुलिस से बचने पांच घंटे तक तालाब में छिपा रहा

जबलपुर। दोपहर मेट्रो

जबलपुर के समीपस्थ एक मोस्ट वांटेड चोर पांच घंटे तक तालाब में छिपे रहने और कमल की डंडी से सांस लेने वाले चोर को लेकर कई खुलासे सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार उसने गोताखोरों और पुलिस कर्मियों से बचने के लिए उन पर हमला भी किया। लेकिन भागने में असफल रहा। 7 अप्रैल को खितौला थाना पुलिस, गोताखोरों और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हरविंदर सिंह को तालाब में छिपे हुए पकड़ा गया। अब उसे रेलवे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पूछताछ के लिए भोपाल-इटारसी जीआरपी पुलिस को सौंप दिया गया है।

जल गंगा संवर्धन अभियान को चुनौती

जाखला नदी का अस्तित्व मिटाने का प्रयास जारी

औबेदुल्लागंज। दोपहर मेट्रो

एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी ओर औबेदुल्लागंज में जाखला नदी का अस्तित्व मिटाने की सुपारी ले ली गई है। नदी के कैचमेंट एरिया में धड़ल्ले से हो रहा मिट्टी भराव प्रशासन की मंशा और दावों पर सीधा प्रहार है। नदी किनारे सक्रिय भू-माफिया और प्लॉट संचालक प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे हैं। जिस नदी को संवारने के लिए सरकारी खजाना खुला है, वहां खुलेआम जल भराव क्षेत्र को पाटा जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले भी नदी का रास्ता मोड़ा जा चुका है, लेकिन राजस्व और जल संसाधन विभाग की रहस्यमयी चुप्पी ने माफियाओं के हौसले बुलंद कर दिए हैं। यदि समय रहते यह अवैध भराव नहीं रुका, तो बारिश में जाखला नदी उफान पर आकर आबादी को डुबो देगी। क्या प्रशासन किसी बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगा रहे इन लापरवाह अधिकारियों और अतिक्रमणकारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की दरकार है, वरना जाखला नदी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी।

गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर घर घर पहुंच रहे गौ सेवक

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहे सेवा, सुरक्षा और सम्मान के तहत गौ सम्मान आह्वान अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए गौ सेवक लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर गौ सेवकों ने लोगों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया तथा दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर अभियान में सहभागिता भी सुनिश्चित करवाई। गौ सेवकों द्वारा सभी सनातन धर्म प्रेमियों, गौ माता के भक्तों एवं गौ रक्षकों से अपील की जा रही है कि वे इस अभियान से जुड़कर गौ संरक्षण के इस महाअभियान को सफल बनाएं। अभियान के तहत आगामी 27 अप्रैल को संपूर्ण भारतवर्ष में जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर पहुंचकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। इसी क्रम में गौ रक्षा मंच के जिला अध्यक्ष विशाल वैष्णव के नेतृत्व में मुकेश सोनी, देवेंद्र सिंह रघुवंशी, पूजा अग्रवाल, दिनेश प्रजापति, धर्मेंद्र मिश्रा, अमन सोनी, सुनीता वैष्णव, दीपिका वैष्णव, अंकित वैष्णव एवं प्रियंका वैष्णव सहित कई कार्यकर्ता अभियान को सफल बनाने और लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

महुआ बीनते समय बाघ का शिकार बना मजदूर, क्षत-विक्षत मिला शव

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के चूरना रेंज में बाघ ने महुआ बीन रहे 49 वर्षीय सुधराम चौहान पर हमला कर उन्हें शिकार बना लिया। बुधवार को हुई इस घटना में सुधराम का क्षत-विक्षत शव गुरुवार सुबह जंगल में मिला। दर्दनाक बात यह है कि 9 अप्रैल को ही उनकी बड़ी बेटी रीना की लग्न मांदीखोह गांव से आनी थी। पिता के शव को पोटली में लिपटे घर पहुंचाने से शादी वाले आंगन में मातम पसर गया।चनागढ़ निवासी सुधराम बुधवार सुबह करीब 11 बजे साथी गुड्डू गोंड के साथ नाव से तवा नदी पार कर एसटीआर के पुराने चनागढ़ फॉरेस्ट क्षेत्र में महुआ बीनने गए थे। शाम को गुड्डू लौट आया, लेकिन सुधराम नहीं पहुंचे। परिजन और ग्रामीणों ने पूरी रात जंगल में उनकी तलाश की, मगर एसटीआर प्रबंधन को देर रात तक खबर नहीं मिली। गुरुवार सुबह 8 बजे 10-12 ग्रामीण तवा नदी से 500 मीटर दूर पहुंचे, तो बाघ की दहाड़ सुनाई दी। खोजबीन में जंगल में सुधराम का शव मिला। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ जंगल में भागा। शव इतना क्षत-विक्षत था कि केवल सिर, सीना और एक पैर बचे थे। पहचान कपड़ों से हुई। एसटीआर टीम और पुलिस ने जंगल से दूसरा पैर बरामद कर पोस्टमार्टम कराया। सुधराम घर की एकमात्र कमाने वाली उम्मीद थे। उनके चार बेटियां और एक बेटा है। 29 अप्रैल को छोटी बेटी की लग्न आने वाली थी, अब घर में सिसकियां और सन्नाटा छाया है। राखी नंदी ने कहा कि यह बाघ द्वारा शिकार की दुखद घटना है। हमारे डॉक्टर पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहे। घटनास्थल के आसपास के कैमरे चेक किए जा रहे हैं। ग्रामीणों से अपील है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश न करें।

मेट्रो एंकर

सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान विधायक ने किया लोगों को संबोधित, कहा-

सड़क निर्माण और आधुनिक खेती से बदल रहा ग्रामीण विकास का परिदृश्य

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार द्वारा चौमुखी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें ग्रामीण और किसान विकास पर विशेष जोर है। कृषि प्रधान देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसानों को आधुनिक एवं उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

ग्रामीण अंचलों को मुख्य मार्गों और शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है, जो ग्रामीण विकास की नई इबारत लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह बात गंजबासौदा विधायक हरिसिंह रघुवंशी ने सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। विधायक रघुवंशी ने ग्राम पवई से ग्राम हिरनोंदा तक आधा किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन किया, जिसका निर्माण लगभग 43.5 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम करारी से करौंदा खुर्द तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क का भी भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ 83 लाख रुपये है। इन विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं विधायक हरिसिंह रघुवंशी के प्रति आभार व्यक्त किया।

रायसेन कृषि मेला किसानों के लिए बनेगा 'गेम चेंजर'

विधायक रघुवंशी ने 11 से 13 अप्रैल तक रायसेन के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय कृषि मेले को किसानों के लिए 'गेम चेंजर' बताया। इस मेले में किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज, खाद प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने के नवीन तरीकों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेले में ड्रोन तकनीक के माध्यम से बीज एवं दवा छिड़काव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कृषक हितैषी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ भी किसानों को मिलेगा, जो उनके विकास में मील का पत्थर साबित होगा। विधायक ने क्षेत्र के किसानों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में रायसेन कृषि मेले में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं।

35 साल में बदली तस्वीर: घने जंगल से बंजर होते वन क्षेत्र

आजीविका और अवैध कटाई ने छीनी जंगलों की हरियाली

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

उपवन मंडल के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों में कभी प्राकृतिक वन संपदा का अपार भंडार हुआ करता था, जो आज तेजी से समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। लगभग 35 वर्ष पूर्व इन जंगलों में तेंदू, हर्र, बहेरा, आँवला, महुआ, कंजी तथा अचार (चिरौंजी) के पेड़ों की भरपूर उपलब्धता थी। यह वन क्षेत्र न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध था, बल्कि ग्रामीणों की आजीविका का भी प्रमुख आधार हुआ करता था। ग्रामीण अंचलों के लोगों के लिए ये वनस्पतियां आय का एक महत्वपूर्ण साधन थीं।

विशेष रूप से अचार के पेड़ों से प्राप्त उत्पादों से ग्रामीणों को अच्छा खासा मुनाफा होता था। उस समय लोगों को मजदूरी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बल्कि वे वन उपज के सहारे ही अपने परिवार का भरण-पोषण आसानी से कर लेते थे। हालांकि, समय के साथ परिस्थितियां

बदलती चली गईं। वन क्षेत्रों में इन उत्पादन देने वाले पेड़ों पर अंधाधुंध कटाई, वन माफियाओं की सक्रियता तथा आजीविका के सीमित विकल्पों के चलते ग्रामीणों द्वारा भी पेड़ों की कटाई बढ़ी। परिणामस्वरूप पिछले 35 वर्षों में लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक वन क्षेत्र की फल फूल देने वाले पेड़ो की हरियाली नष्ट हो चुकी है। सबसे अधिक नुकसान अचार ,आँवला, तेंदू, हर्र ,बहेरा के पेड़ों को हुआ है, जिन पर सबसे ज्यादा कुल्हाड़ी चली। आज स्थिति यह है कि कभी घने और समृद्ध रहे इन जंगलों में गिने-चुने पेड़ ही शेष रह गए हैं। वन परिक्षेत्रों की यह बदहाल स्थिति पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे का संकेत दे रही है। जैव विविधता में कमी, जल स्रोतों पर प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि वन संरक्षण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही ग्रामीणों को वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे जंगलों पर निर्भरता कम कर सकें। जनजागरूकता, सख्त निगरानी और पुनर्वनीकरण जैसे प्रयासों के माध्यम से ही इस प्राकृतिक धरोहर को बचाया जा सकता है। उपवन मंडल के जंगलों की यह स्थिति एक चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को यह समृद्ध वन संपदा केवल कहानियों में ही सुनने को मिलेगी।

न्यूज विंडो

एचपीवी मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम की तैयारी के लिए बैठक संपन्न

तेंदूखेड़ा। नगर के सांदीपनि हायर सेकेंडरी विद्यालय में समस्त मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी एचपीवी लक्षित मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक में विकासखंड शिक्षा अधिकारी नितेश पांडे ने कार्यक्रम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। बीईओ पांडे ने कहा कि एचपीवी टीकाकरण किशोरियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एचपीवी टीकाकरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (सर्वाइकल कैंसर) से बचाव करता है। भारत सरकार ने 14 साल की लड़कियों के लिए एक विशेष एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार एक खुराक (सिंगल डोज) योजना अपनाई जाएगी। हर साल लगभग 1.15 करोड़ लड़कियां 14 वर्ष की उम्र पूरी करती हैं और सभी इस टीके के लिए पात्र होंगी। बैठक में बताया गया कि विकासखंड स्तर पर एचपीबी टीकाकरण हेतु मेगा शिविरों का आयोजन क्रमशः 11 अप्रैल, 15 अप्रैल, 21 अप्रैल एवं 27 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में लगभग 500 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री पांडे ने प्रधानाध्यापकों से अपील की कि वे बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। इस दौरान बीआरसी पीएल अहिरवार ,जनशिक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग से भी उपस्थित रहे।

प्रतिबंध के बाद भी जारी अवैध खनन, बोर मशीन संचालकों की दबंगई से उठे सवाल

अनूपपुर/शहडोल/उमरिया। संभाग के तीनों जिलों में नलकूप (बोरिंग) खनन पर जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद अवैध गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सामने आया है जहां प्रतिबंध के बाद भी बोरिंग मशीनों के जरिए खनिज दोहन जारी है, जिससे नियमों की खुली अनदेखी हो रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह अवैध खनन कार्य ज्यादातर रात के अंधेरे में किया जा रहा है, ताकि प्रशासन की नजर से बचा जा सके। भारी मशीनों और वाहनों की आवाजाही से ग्रामीणों को इसकी जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन कार्रवाई के अभाव में यह सिलसिला लगातार जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा, शिकायत करने वालों को बोर मशीन संचालकों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तो शिकायतकर्ता भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह का अवैध बोरिंग आधारित खनन भूजल स्तर को तेजी से गिरा सकता है, जिससे भविष्य में जल संकट गहराने की आशंका है। इसके अलावा, भूमि धंसने और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन द्वारा स्पष्ट प्रतिबंध लागू है, तो फिर भी इस तरह की अवैध गतिविधियां कैसे फल-फूल रही हैं? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी या मिलीभगत इस पूरे मामले के पीछे है।

खैर माफिया का भंडाफोड़ या विभाग की मिलीभगत: वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

पकड़ी थी अवैध खैर की लकड़ी, विभाग ने जिसे मकान बताया वो निकला कारखाना

धार। दोपहर मेट्रो

वनमंडल धार के अंतर्गत अवैध खैर लकड़ी के कारोबार पर हाल ही में की गई छापेमारी अब वन विभाग के लिए ही गले की फांस बनती नजर आ रही है। वनमंडलाधिकारी विजयानंथम टी.आर. के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई ने सफलता का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर विभाग के अंदरूनी तंत्र और माफिया के बीच गठजोड़ की चर्चाओं ने वन विभाग की साख पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

दरअसल 7 अप्रैल की अलसुबह सरदारपुर क्षेत्र के लाबरीया-चिराखान स्थित लाल्याखाल में एक मकान पर वन विभाग की टीम ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान लगभग 50 से 60 क्विंटल खैर लकड़ी और 4 पिकअप वाहन जब्त किए गए। विभाग ने लकड़ी की अनुमानित कीमत 2 से ढाई लाख रुपए बताई है। मौके से छतरपुर निवासी दो मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि वे शाहरुख और बादशाह नामक व्यक्तियों के लिए पिछले 15 दिनों से लकड़ी छीलने का काम कर रहे थे।

मकान या अवैध कारखाना?

विभाग जिस जगह को मकान बता रहा है, ग्रामीणों का दावा है कि वहां लंबे समय से खैर लकड़ी को प्रोसेस करने का कारखाना फल-फूल रहा था। सवाल यह है कि महीनों से चल रहे इस अवैध काम की भनक बीट गार्ड और क्षेत्रीय अमले को क्यों नहीं लगी। सूत्रों का आरोप है कि मौके से जब्त लकड़ी की वास्तविक मात्रा बहुत अधिक थी, लेकिन विभागीय कागजों में इसे कम करके दिखाया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्र तक कैसे पहुंची। रास्ते में पड़ने वाली नाकों और गश्ती दलों की आंखों में धूल झोंककर यह परिवहन कैसे संभव हुआ।

मिलीभगत की चर्चाएं गर्म

क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है कि खैर माफिया को विभाग के ही कुछ निचले और मध्यम स्तर के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। बिना ऊपर की सेटिंग के इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी का भंडारण और प्रोसेसिंग मुमकिन नहीं है। फरार मुख्य आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होना भी संदेह को गहरा रहा है। अब नजरें वनमंडल अधिकारी विजयानंथम टी.आर. पर टिकी हैं। क्या वे इस मामले की गहराई से निष्पक्ष जांच करवाकर अपने ही विभाग के भीतरघातियोंको बेनकाब करेंगे? या फिर यह मामला भी महज चंद क्विंटल लकड़ी और कुछ मजदूरों की गिरफ्तारी तक सिमट कर रह जाएगा।

प्रशासन पर उठे सवाल

राजेंद्रग्राम में अवैध प्लेन मसाला निर्माण का खेल

अनूपपुर। दोपहर मेट्रो

जिले की राजेंद्रग्राम तहसील क्षेत्र में प्लेन मसाला के नाम पर अवैध रूप से उत्पादों के निर्माण और बिक्री का मामला सामने आ रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कुछ स्थानों पर ब्रांड की नकल करते हुए मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिसे संरक्षण में बाजार में खपाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह गतिविधि लंबे समय से जारी है, लेकिन अब तक संबंधित विभागों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस अवैध कारोबार से शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है, साथ ही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के कारण यह अवैध काम बेखौफ जारी है। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

कृषि मंडी से जीतू पटवारी ने फोन पर कलेक्टर से कहा-

किसान यहां बदहाल है और प्रशासन सुध तक नहीं ले रहा

सागर। दोपहर मेट्रो

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कृषि मंडी रोड पर किसानों का हुजूम देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया। अपनी उपज के सही दाम न मिलने और मंडी प्रबंधन की उदासीनता से नाराज किसान पिछले तीन-चार दिनों से मंडी में डटे हुए थे। किसानों की आपबीती सुनते ही पटवारी ने मौके से ही सागर कलेक्टर संदीप जी आर को फोन लगाकर दो टूक शब्दों में कहा कि किसान यहां बदहाल हैं और प्रशासन सुध तक नहीं ले रहा है। कलेक्टर तुरंत मंडी आकर स्थिति देखें। पटवारी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का किसान कल्याण वर्ष वास्तव में शोषक वर्ष बन गया है। मंडी में किसानों के बीच पहुंचे पटवारी ने कलेक्टर संदीप जी आर की बात सीधे मंडी प्रबंधन से कराई और समस्याओं के तत्काल

निराकरण करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसान फसलों के दाम और बारदाने के लिए दर-दर भटक रहा है। इस दौरान जिला ग्रामीण अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मुहासा ने भी कहा कि पटवारी की मेहनत और कांग्रेसियों का साथ जल्द ही सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगा। शहर अध्यक्ष महेश जाटव ने पटवारी को जनता की उम्मीद बताते हुए कहा कि उनके सागर आगमन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जीतू पटवारी ने कहा की मोदी की गारंटी खत्म हो गई है. नेता सागर का खुरई ,रहली ,सुरखी नरयावली कहीं का भी नेता हो सभी एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा के नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखें। हम सबको मिलकर पीड़ित जनता के हित में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने एकजुट होकर काम करना होगा। जनता को परेशान करने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुनील जैन,अमित राम जी दुबे, प्रदीप गुप्ता, मुकुल पुरोहित, सिंटू कटारे, हेमराज रजक, नरेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र राजे, आनंद हेला, सागर साहू , राहुल चौबे, बब्बू यादव, कमलेश तिवारी, समीर खान, प्रशांत समैया समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मेट्रो एंकर | जिम्मेदार अधिकारी नदारद, छोटे कर्मचारी चला रहे 33 करोड़ की जल योजना

मनमाने समय पर पानी सप्लाई से जनता परेशान

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

नगर में पेयजल संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है। लगभग 45 किलोमीटर दूर लम्हेटाघाट से लाई गई नर्मदा जल परियोजना, जिसकी लागत लगभग 33 करोड़ रुपये बताई जाती है, आज भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की भेंट चढ़ती नजर आ रही है इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य नगरवासियों को नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके ठीक विपरीत है।

नगर में कोई जिम्मेदार अधिकारी तैनात नहीं होने के कारण पूरी व्यवस्था छोटे कर्मचारियों के भरोसे चल रही है, जो अपनी मनमर्जी से जल वितरण कर रहे हैं। पानी सप्लाई का न तो कोई निश्चित समय तय है और न ही कोई निर्धारित दिन कहीं 3 दिन में पानी दिया जा रहा है तो कहीं 5 दिन में, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कर्मचारियों द्वारा लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि

सुबह नल खुलेंगे, तो कभी 11 बजे या शाम 5 बजे का समय बताया जाता है, लेकिन अधिकांश समय लोग खाली बर्तन लेकर इंतजार ही करते रह जाते हैं लेकिन समय पर पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है इससे नागरिकों में आक्रोश और असंतोष बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से नगर के वार्ड 9 की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जहां पिछले 6 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। लगभग सैकड़ों परिवार पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लोगों को मजबूर होकर दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे उनकी दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है नगरवासियों ने मांग की है कि इस योजना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जल आपूर्ति के लिए एक निश्चित समय और दिन निर्धारित किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और जनता को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है इधर नर्मदा परियोजना के साइड इंजीनियर द्वारा अपनी मनमानी करते हुए नजर आए जहां लोग पानी के 24 घंटे तक इंतजार करते रहे।

वार्डवासी पहुंचे नगर परिषद लेकिन सुनने वाला कोई नहीं

सुबह वार्ड 9 के कुछ लोग पानी की शिकायत को लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे जहां उन्हें नगर परिषद कार्यालय में बने नर्मदा परियोजना के कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौटते हुए नजर आए लेकिन उसी समय नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश कुमार जैन की नजर लोगों पर पड़ी तो उन्होंने सभी लोगों को अपने कार्यालय में बुलाया जहां वार्ड क्रमांक 9 के लोगों की समस्या सुनकर पानी की व्यवस्था मे जल्द ही सुधारने का आश्वासन दिया और नर्मदा परियोजना के कर्मचारियों से बात करके फोन पर फटकार लगाई।

कार्यालय नगर पालिक निगम सागर

दूरभाष क्रमांक/फेक्स क्रमांक-07582-229454, 07582-224553,
ई-मेलः (commsagar@mpurban.gov.in)
ULB Code-802159

क्र./न.नि./स्व.भा.मि./2026/56 सागर दिनांक 9.4.26

सार्वजनिक सूचना

IS 2470 मानकों के अनुसार सेप्टिक टैंक निर्माण संबंधी

नगर पालिक निगम सागर क्षेत्र के समस्त नागरिकों/भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि जिन परिसरों में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहाँ सेप्टिक टैंक का निर्माण करना अनिवार्य है। अमानक सेप्टिक टैंक, या बिना उपचारित जल का खुले में/नालियों में प्रवाह पूर्णतः प्रतिबंधित है।

सेप्टिक टैंक का निर्माण निम्न मानकों के अनुसार किया जाना आवश्यक है:-

IS 2470(Part 1) : सेप्टिक टैंक की नियमानुसार डिजाइन एवं निर्माण

IS 2470(Part 2) : अपशिष्ट जल का निस्तारण

निर्धारित समयावधि में सभी को उक्त मानकों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, सागर

आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स बनाम गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच मुकाबला

आरसीबी और रॉयल्स के शीर्षक्रम के बल्लेबाजों पर रहेंगी नजरें

गुवाहाटी, एजेंसी

यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी से मिल रही आक्रामक शुरूआत के साथ राजस्थान रॉयल्स शुक्रवार को यहां गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ आईपीएल के मैच में अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी जबकि आरसीबी की उम्मीदें फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल पर टिकी होंगी। दो साल पहले टी-20 क्रिकेट से विदा लेने के बावजूद आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के प्रदर्शन में कमी नहीं आई है। उनके मार्गदर्शन में आरसीबी ने संतुलित शीर्षक्रम तैयार कर लिया है और पिछले मैच में फिल साल्ट ने भी उम्दा पारी खेली थी। तीसरे नंबर पर उतर रहे पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट का अपना फॉर्म कायम रखते हुए संतुलित आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी की है। आईपीएल में अपने पदार्पण सत्र में आरसीबी के लिये 473 रन बनाने वाले पडिक्कल बाद में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स के साथ उस सफलता को दोहरा नहीं सके थे। पिछले सत्र में वह आरसीबी में लौटे और पहली बार उसे आईपीएल खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस सत्र में भी उन्होंने पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 29 गेंद में 50 और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 26 गेंद में 61 रन बनाये। कप्तान रजत पाटीदार और आस्ट्रेलिया के टिम डेविड मध्यक्रम को मजबूती देते हैं।

दिल्ली में आईपीएल टिकटों की का आरोप

नयी दिल्ली। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के निदेशक आनंद वर्मा ने आरोप लगाया कि वैध टिकट धारकों को अरूण जेटली स्टेडियम पर आईपीएल मैचों के दौरान अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश से रोक रहे हैं जिन्होंने धोखेबाजी से नकली टिकट हासिल किये हैं जबकि डीडीसीए के आला अधिकारियों ने इस आरोप का खंडन किया है। पुलिस उपायुक्त (मध्य जिला) से की गई शिकायत में वर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके मेहमानों को चार अप्रैल को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच के दौरान स्टेडियम के हॉस्पिटेलिटी हिस्से में प्रवेश नहीं करने दिया गया जबकि उनके पास वैध टिकट थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें दिये गए टिकट का इस्तेमाल अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पहले ही किया जा चुका था। डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने हालांकि इसे तकनीकी मसला बताया। वर्मा ने कहा, वादी और उनके मेहमान जब प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्हें अवैध तरीके से रोक दिया गया और वहां खड़े सुरक्षार्किमयों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा, जांच के बाद पता चला कि उनके पास मौजूदा दो मानार्थ टिकट पहले ही स्कैन हो चुके थे और अनधिकृत तथा अज्ञात व्यक्तियों ने उनका प्रयोग कर लिया था।

कौन हैं मुकुल चौधरी? जिन्होंने छक्कों की बारिश कर पलटा मैच

लखनऊ के खिलाफ चारों खाने चित हुई कोलकाता, आखिरी गेंद पर मिली हार

कोलकाता, एजेंसी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 15वें मुकाबले में गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने-सामने हुईं। ईडन गार्डन्स में आयोजित इस हाई-वोल्टेज मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। कोलकाता ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के सामने 182 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे मेहमान टीम ने मैच की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के हीरो रहे 21 साल के मुकुल चौधरी रहे, जिन्होंने दबाव भरे मुकाबले में 27 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाकर मैच को पलट दिया। उनकी इस पारी में 7 छक्के और 2 चौके शामिल रहे। लखनऊ की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय मुश्किल में नजर आ रही थी। 128 रनों के स्कोर तक उसके सात विकेट गिर चुके थे और जीत लगभग कोलकाता के पाले में जा चुकी थी।

यहां से मुकल चौधरी ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। 17वें ओवर में मुकुल चौधरी ने वैभव अरोड़ा को चौका और छक्का लगाया। फिर उन्होंने 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी को दो छक्के लगाए। मुकुल ने 19वें ओवर में कैमरन ग्रीन को भी नहीं बख्शा। ग्रीन के उस ओवर में मुकुल ने दो छक्के जड़ने के अलावा एक चौका भी लगाया। लखनऊ को अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रन चाहिए थे। वैभव अरोड़ा के उस ओवर में आवेश खान ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मुकुल ने छक्का लगाकर प्रेशर कम किया इसके बाद वैभव ने लगातार दो गेंद डॉट डाली। फिर मुकुल ने पांचवीं गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। आखिरी गेंद पर 1 रन बनाने थे। मुकल आखिरी गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो बाय के तौर पर सिंगल लेने में जरूर कामयाब रहे, जिसके चलते लखनऊ की टीम ने मैच जीत लिया।

आक्रामक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं मुकुल

मुकुल चौधरी दाएं हाथ के आक्रामक मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। मुकुल का जन्म 6 अगस्त 2004 को राजस्थान के झुंझुनू हुआ था। मुकुल राजस्थान के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। मुकुल ने अब तक 4 फर्स्ट क्लास, 5 लिस्ट-ए और 10 टी20 मुकाबले खेले हैं। फर्स्ट क्लास मैचों में मुकुल ने 17.16 की औसत से 103 रन बनाए हैं। वही लिस्ट-ए क्रिकेट में मुकुल के नाम पर 14.20 की औसत से 71 रन दर्ज हैं। टी20 क्रिकेट में मुकुल ने 46।66 और 164।70 की स्ट्राइक रेट से 280 रन स्कोर किए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल रहे। मुकुल चौधरी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में तूफानी बैटिंग कर सुर्खियां बटोरी थीं। तब मुकुल ने पांच पारियों में 57.66 के एवरेज और 198।85 की स्ट्राइक रेट से 173 रन बना दिए थे, जिसमें 10 चौके और 13 छक्के शामिल रहे। आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में मुकुल को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2।60 करोड़ रुपये में खरीदा। मुकुल का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था।

केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रघुवंशी ने बनाए 45 रन

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की बात करें, तो अंगकृष रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। वहीं कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 24 बॉल पर 41 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। रोवमैन पॉवेल (नाबाद 39 रन) और कैमरन ग्रीन (नाबाद 32 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिए। ग्रीन और पॉवेल की 70 रन की साझेदारी ने टीम को 181 रनों तक पहुंचाया। रनचेज में लखनऊ की शुरुआत अच्छी रही और 41 रनों के स्कोर पर उसका पहला विकेट गिरा। सलामी बल्लेबाजों एडेन मार्करम ने 22 और मिचेल मार्श ने 15 रन बनाए। ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद लखनऊ के विकेट्स गिरते चले गए। कप्तान ऋषभ पंत (10 रन), निकोलस पूरन (13 रन) और अब्दुल समद (2 रन) कुछ खास नहीं कर सके।

कोहली का नाम सुनते ही भड़के बाबर आजम, पत्रकार को लगाई फटकार

कराची, एजेंसी

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में बुधवार (8 अप्रैल) को कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर जाल्मी का सामना हैदराबाद किंग्समेन से हुआ. इस मुकाबले में बाबर आजम की अगुवाई में पेशावर जाल्मी ने 146 रनों का लक्ष्य छह विकेट खोकर आखिरी गेंद पर हासिल किया.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने बाबर आजम से पूछा कि उनकी तुलना अक्सर विराट कोहली से की जाती है, लेकिन कोहली मैच फिनिश करने में ज्यादा सफल माने जाते हैं. यह सवाल सुनते ही बाबर बेहद नाराज हो गए. बाबर ने जवाब देते हुए कहा, %यह यहीं खत्म करें, ऐसी बातें अपने पास रखें. तुलना बंद करें. यह आपकी गलतफहमी है कि मैंने मैच फिनिश नहीं किए.% बाबर का यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैन्स के बीच बहस छिड़ गई. इस मुकाबले में बाबर आजम ने पेशावर जाल्मी को मजबूत शुरुआत दिलाई. बाबर ने 37 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल रहे. बाबर ने इस दौरान कुसल मेंडिस के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी की. हालांकि 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम के आउट होने के बाद मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया. अंत में इफ्तिखार अहमद (नाबाद 15 रन) की शानदार बल्लेबाजी ने टीम को जीत दिला दी.

PSL 2026 में बाबर का कैसा रहा है प्रदर्शन?

पाकिस्तान सुपर लीग के मौजूदा सीजन में बाबर आजम ने अब तक 2 मैचों में 41.00 की औसत और 126.15 की स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए हैं. इस जीत के साथ पेशावर जाल्मी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है. अब पेशावर जाल्मी का अगला मुकाबला कराची किंग्स से होना है. बाबर आजम और विराट कोहली की तुलना लंबे समय से होती रही है. दोनों बल्लेबाज अपनी क्लासिक बल्लेबाजी, निरंतरता और बड़े रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाते हैं. 2021 में बाबर ने हृष्ड्ड रैंकिंग में कोहली को पीछे छोड़ा. फिर 2023 सबसे तेज 5000 ODI रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. हालांकि, बाबर कई बार कोहली के प्रति सम्मान जता चुके हैं और उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजो में से एक मानते हैं. पेशावर जाल्मी की जीत के बावजूद बाबर आजम का यह गुस्सा दिखाता है कि लगातार तुलना का दबाव खिलाड़ियों पर कितना असर डालता है.

हार से बौखलाए मेदवेदेव ने सात बार रैकेट फेंका

मोनाको। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में मातेओ बेरेत्तिनी से 6-0, 6-0 से मिली हार के बाद अपना रैकेट सात बार लाल क्लेकोर्ट पर फेंका। इस समय दसवीं रैंकिंग पर काबिज मेदवेदेव 49 मिनट में मुकाबला हार गए। उन्होंने पांच डबल फॉल्ट किये जबकि बेरेत्तिनी ने एक भी नहीं किया। मेदवेदेव इस साल क्ले पर अपना पहला मैच खेल रही थी। उन्होंने हाल ही में इंडियन वेल्स में हार्डकोर्ट पर शीर्ष रैंकिंग वाले कार्लोस अल्काराज को हराया था।

मनोरंजन **बॉलीवुड का कोना**

हंसिका मोटवानी ने एक्स भाभी पर किया मानहानि का केस?

एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ और कोर्ट केस को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उनके नाम से जुड़ा एक मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आइए जानते हैं क्यों एक्ट्रेस इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हंसिका ने अपनी अलग रह रही एक्स भाभी और टीवी एक्ट्रेस मुस्कान नैन्सी जेम्स के खिलाफ मुंबई कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया है। उन्होंने इस केस में 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है और साथ ही पब्लिक माफी की भी मांग की है। हंसिका का आरोप है कि उनकी भाभी ने सोशल मीडिया पर उनके

पब्लिक माफी के साथ की 2 करोड़ के हर्जाने की मांग

खिलाफ गलत और नुकसान पहुंचाने वाले आरोप लगाए, जिससे उनकी इमेज खराब हुई। एक्ट्रेस का यह भी कहना है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि करीब 27 लाख रुपये के उधार पैसे वापस न करने पड़ें।

मुस्कान ने लगाए थे हंसिका पर गंभीर आरोप

वहीं दूसरी तरफ, मुस्कान नैन्सी जेम्स ने पहले हंसिका और उनके भाई पर घरेलू हिंसा और उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। हंसिका ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। उनका कहना है कि उनका अपने भाई और भाभी के घरेलू मामलों से कोई लेना-देना नहीं था, इसलिए उन्हें इस मामले में घसीटना ठीक नहीं है। अब यह मामला कोर्ट में है और आने वाले समय में इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल, यह पूरा विवाद सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

कश्मीरी कुर्ता और हरियाणवी बोल

भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने आख्या में आख घाली गाने पर लगाए ठुमके

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कला के क्षेत्र में भाषा संबंधी सीमाओं को तोड़ने का काम बखूबी किया है। अब बॉलीवुड सितारे भोजपुरी गानों पर डांस करते दिखते हैं तो भोजपुरी सितारों पर हरियाणवी म्यूजिक का रंग चढ़ा है। हाल ही में रानी चटर्जी ने भी हरियाणवी गाने पर जबर्दस्त डांस किया।

भोजपुरी म्यूजिक का अपना अलग आकर्षण है। ये अब सिर्फ क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देशभर में भोजपुरी गाने पसंद किए जाते हैं। इसी तरह, हरियाणवी सॉन्ग भी संगीत प्रेमियों की पसंदीदा लिस्ट में जगह बना रहा है। हाल ही में रानी चटर्जी आख्या में आख घाली घाली गाने पर धमाकेदार डांस करती दिखीं। उन्होंने हरे रंग का कश्मीरी कुर्ता पहना

हुआ है। रानी चटर्जी ने अपना डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। इसके साथ कैप्शन लिखा है, कश्मीरी कुर्ता ते हरियाणवी बोल। उफ्फ मैं तो शरमा गई। उन्होंने अपनी कुछ फोटोज भी शेयर की हैं और लिखा है, नजर ना लग जाए। रानी चटर्जी ने डार्क रेड लिपस्टिक और हैवी आई मेकअप से अपना लुक कंपलीट किया है। रानी के पोस्ट पर नेटिजंस रिएक्शन दे रहे हैं और उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं, सुपर डांस परफॉर्मेंस। एक अन्य यूजर ने लिखा, सुपर से भी ऊपर। कुछ फैंस उन्हें लीजेंड बता रहे हैं। तमाम यूजर्स फायर और रेड हार्ट इमोजी बनाते दिख रहे हैं। बता दें कि रानी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

मेट्रो बाजार

भारत के लिए ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स में विविधता लाने में कई चुनौतियां, बोले टाटा स्टील के सीईओ

नई दिल्ली। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए मजबूत करने के उद्देश्य से ऊर्जा के नए स्रोतों और क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हालांकि, एक तरफ जहां यह डायवर्सिफिकेशन देश के लिए बेहद जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ इसने कुछ नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है। गुरुवार को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) लीडरशिप कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने भारत के इस रणनीतिक कदम को बहुस्तरीय जोखिम करार दिया। टीवी नरेंद्रन के अनुसार भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए सप्लाई चेन में पैदा होने वाले नए जोखिमों को भी समझना आवश्यक है। नरेंद्रन ने कहा कि ऊर्जा और क्रिटिकल खनिजों के स्रोतों में विविधता लाना भारत के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें छिपी जटिलताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, यह चुनौती बिल्कुल साफ है। हम ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोतों में विविधता ला रहे हैं, जो कि हमें करना ही चाहिए; लेकिन यह डायवर्सिफिकेशन एक बहुस्तरीय जोखिम भी है। यह केवल आयात पर निर्भरता जैसी चुनौती नहीं है, बल्कि यह उन रणनीतिक फैसलों पर भी जुड़ा निर्भर करती है जो इन आयातों को सुचारू रूप से हमारे देश तक पहुंचने देती है।वैश्विक

माल ढुलाई में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में रेलवे 2020 के लिए तय किया ये बड़ा टारगेट

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में भारतीय रेलवे की भूमिका आने वाले वर्षों में और ज्यादा अहम होने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश ने 2030 तक 3,000 मिलियन टन माल ढुलाई क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। जिसमें रेलवे की बड़ी भूमिका होगी।

एसोचैम-एईएससीएलए की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है। जो आगे बढ़ने की बड़ी संभावनाएं दिखाती है। रेलवे सेक्टर इस समय तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाओं और लगभग पूरी हो चुकी विद्युतीकरण प्रक्रिया से रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ी है और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी मजबूत हुई है। इन सुधारों की वजह से अब माल ढुलाई पहले से ज्यादा तेज, सस्ती और भरोसेमंद हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्षमता बढ़ाना, फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार, निजी क्षेत्र की भागीदारी और बेहतर लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर खास ध्यान देना जरूरी है। साथ ही लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल यह देश की जीडीपी का करीब 7.97 फीसदी है।अगर इस लागत को कम किया जाता है, तो भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा।

भारत रेलवे हर साल कितनी माल ढुलाई कर रहा है?- भारतीय रेलवे पहले ही हर साल 1.6 अरब टन से ज्यादा माल ढुलाई कर रहा है और आने वाले समय में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, नीतिगत सुधार और डिजिटलीकरण की वजह से रेलवे सेक्टर देश की आर्थिक प्रगति का एक मजबूत आधार बनता जा रहा है।

अंतरिक्ष में इतिहास रचने के करीब भारत!

श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 'गगनयान' की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी है कि इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया।

गगनयान के दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट में इसरो को शानदार कामयाबी

IADT का पूरा नाम Integrated Air Drop Test (एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण) है। गगनयान मिशन का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाना है। जब अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा करके वापस लौटेंगे, तो उनका 'क्रू मॉड्यूल' (वह कैप्सूल जिसमें वे बैठे होंगे) तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। इस वापसी के दौरान पैराशूट सिस्टम की भूमिका अहम होगी। मॉड्यूल की गति को धीमा करने और उसे सुरक्षित रूप से समुद्र (या सतह) पर उतारने के लिए एक बेहद जटिल पैराशूट प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। IADT परीक्षण के दौरान एक डमी क्रू मॉड्यूल को भारतीय वायुसेना के किसी भारी विमान या हेलीकॉप्टर की मदद से कई किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह जांचना होता है कि क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सही समय पर, सही क्रम में और बिना किसी तकनीकी खराबी के खुल रहे हैं या नहीं। IADT-02 की सफलता यह साबित करती है कि इसरो का पैराशूट और रिकवरी सिस्टम बिल्कुल सटीक काम कर रहा है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की गारंटी है।

रक्षा मंत्रालय ने बनाया प्लान

स्वदेशी मिसाइलों से लैस होंगे 114 राफेल लड़ाकू विमान

नई दिल्ली। भारत जिन 114 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्लान बना रहा है, उनको लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों और हथियार प्रणालियों को इनमें एकीकृत किया जा सके। मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि खरीदो और बनाओ सौदे के तहत होने वाली सरकार-से सरकार डील में तथाकथित इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट को अनिवार्य किया जाएगा।

डीएसी सौदे को दे चुका है मंजूरी: रक्षा मंत्रालय से उम्मीद है कि वह अगले महीने फ्रांसीसी जेट निर्माता कंपनी डसॉल्ट को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगा और उसके बाद अनुबंध पर बातचीत शुरू होगी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 12 फरवरी को इस सौदे को मंजूरी दे दी थी।

डील में रुकावट: इस तरह की रिपोर्टों के बीच कि इस मेगा डील में एक रुकावट आ गई है, क्योंकि फ्रांसीसी राफेल निर्माता डसॉल्ट ने भारत को लड़ाकू विमान का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कोई भी देश ये मालिकाना सॉफ्टवेयर कोड (जो रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हथियार एकीकरण को नियंत्रित करते हैं) किसी तीसरे देश को नहीं देता है और यह डील पूरी तरह से सही रास्ते पर है।

96 फाइटर जेट भारत में ही बनाए जाएंगे

मामले के जानकार लोगों ने कहा कि योजना यह है कि 3.25 लाख करोड़ रुपये की इस मेगा डील के फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में आईसीडी को पक्का कर दिया जाए। आईसीडी एक बहुत ही जरूरी सिस्टम इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट है, जो किसी सिस्टम और उसके सब-सिस्टम के बीच के सभी अहम प्रोटोकॉल को कंट्रोल और डिफाइन करता है।

चुनावी दंगल : इस बार मुकाबला पार्टियों के बीच कम, कद्दावर मुख्यमंत्रियों के व्यक्तित्व के बीच अधिक

असम में हिमंता तो बंगाल में ममता, चारों राज्यों में विचारधारा पर भारी है चेहरा

नई दिल्ली, एजेंसी

असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनाने के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनावी दंगल में इस बार मुकाबला पार्टियों के बीच कम और इन राज्यों के कद्दावर मुख्यमंत्रियों के व्यक्तित्व के बीच अधिक हो गया है। इन चारों राज्यों में मुख्यमंत्री अपनी पार्टियों से भी बड़े 'ब्रांड' बनकर उभरे हैं, जहां वोट विचारधारा के बजाय सीधे चेहरे के नाम पर मांगे जा रहे हैं।

बंगाल की 'फाइटर' के लिए सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा

पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह अब तक की सबसे कठिन लड़ाई मानी जा रही है। उनके समर्थकों का कहना है कि यह मुकाबला 'ममता बनाम चुनाव आयोग' बन चुका है। आपको बता दें कि एसआईआर के बाद बंगाल में अब तक मतदाता सूची से 91 लाख नाम हटा दिए गए हैं। यदि ममता इस बार भी भाजपा के विजय रथ को रोकने में सफल रहती हैं, तो वह 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष की ओर से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का दावा ठोक सकती हैं।

महिला वोट बैंक की जंग

भाजपा 16-18 अप्रैल के विशेष सत्र में 'महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक' लाकर ममता के महिला कार्ड की काट ढूंढने की कोशिश में है। हालांकि, ममता का भरोसा अब भी उनके मजबूत महिला और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर टिका है।

हिमंत बिस्वा सरमा- असम में भाजपा के संकटमोचक

असम में चुनावी तस्वीर काफी हद तक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के इर्द-गिर्द बुनी गई है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है, लेकिन 'मामा' के नाम से लोकप्रिय हिमंत ने भाजपा के हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को जमीन पर उतारकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भाजपा ने राज्य की 126 सीटों में से 103 हिंदू-बहुल सीटों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है, जबकि 23 मुस्लिम-बहुल सीटों को लगभग कांग्रेस के खाते में छोड़ दिया है। हिमंता भाजपा के उन गिने-चुने मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्हें आलाकमान ने काम करने की पूरी स्वायत्तता दी है, जो आमतौर पर केवल योगी आदित्यनाथ या देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को ही मिलती है।

मतदान के चौंकाने वाले आंकड़े

इस बार के चुनावों में मतदाताओं का उत्साह चरम पर देखा गया है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, असम में 85%, पुडुचेरी में 90% और केरल में 78% मतदान हुआ है।

पिनाराई विजयन- केरल के प्रैग्मैटिक नेता

केरल का इतिहास रहा है कि वहां हर पांच साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन 2021 में पिनाराई विजयन ने इस परंपरा को तोड़कर दोबारा सत्ता हासिल की थी। इस बार वह तीसरी पारी की उम्मीद कर रहे हैं, जो केरल की राजनीति में एक असाधारण उपलब्धि होगी। एक कम्युनिस्ट नेता होने के बावजूद विजयन ने बाजार की शक्तियों और भाजपा शासित केंद्र के साथ व्यवहारिक तालमेल बिठाकर शासन चलाया है। विजयन के लिए यह हार देश में वामपंथी राजनीति को हाशिए पर धकेल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भाजपा अक्सर कांग्रेस की तुलना में विजयन को प्राथमिकता देती दिखती है।

एम के स्टालिन

तमिलनाडु में एम के स्टालिन ने खुद को एक शालीन और मिलनसार नेता के रूप में स्थापित किया है। हालांकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ी है। अभिनेता विजय की पार्टी 'टीवीके' इस चुनाव में 'एक्स-फैक्टर' साबित हो सकती है। यदि विजय युवाओं और बदलाव चाहने वालों का 15% से अधिक वोट काट लेते हैं, तो द्रमुक के लिए त्रिशंकु विधानसभा का खतरा पैदा हो सकता है।

न्यूज विंडो

ऑनलाइन गेमिंग में रकम डूबने पर छात्र ने लगाई फांसी

लखनऊ। लखनऊ के मानकनगर के रामनगर निवासी विशाल सिंह (22) ने फंदा लगा लिया। पुलिस ऑनलाइन गेमिंग में रकम डूबने पर जान देने की बात कह रही है। विशाल के पिता दिनेश सिंह ने बताया कि बेटा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के साथ ट्यूशन पढ़ाता था। कुछ समय से वह परेशान था। पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया था। दोपहर दादी पूनम मकान की दूसरी मंजिल पर गई तो विशाल को कमरे की रोशनदान से गमछे के सहारे लटका देखा। उनकी चीख सुन मां संगीता और अन्य घरवाले भी आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लिया। विशाल का एक भाई और एक बहन है। दोस्त से उधार लिए थे 30 हजार रुपये: दिनेश सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर बेटे का दोस्त घर आया था।

मुंबई एयरपोर्ट पर 37 करोड़ का सोना जब्त, 24 महिलाएं गिरफ्तार

मुंबई। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़े सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 24 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, इनके पास से 29.37 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 37.74 करोड़ रुपये है। अधिकारी ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट ने 'ऑपरेशन धाहाबू ब्लिट्ज' चलाया। इसे इस वर्ष मुंबई एयरपोर्ट पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। 'धाहाबू' स्वाहिली भाषा में सोने को कहा जाता है। अधिकारियों ने बताया, 'डीआरआई को सूचना मिली थी कि केन्या के नैरोबी से आने वाली कुछ महिलाएं अपने साथ सोना छिपाकर ला रही हैं। इसके बाद नैरोबी से मुंबई पहुंची 24 विदेशी महिलाओं को रोका गया। उनकी जांच के दौरान बैग और कपड़ों से 25.10 किलोग्राम सोने की ईंटें और 4.27 किलोग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए।'

हरिवंश नारायण फिर बने राज्यसभा सांसद, राष्ट्रपति ने किया मनोनीत

नई दिल्ली, एजेंसी

जनता दल (यूनाइटेड) नेता हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर से राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का नामित सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। इस बार जदयू की ओर से हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा चुनाव में मौका नहीं दिया गया था।

हालांकि, हरिवंश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब उन्हें दोबारा नामित सदस्य के रूप में राज्यसभा भेज दिया गया है। हरिवंश का उच्च सदन के सदस्य के रूप में कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त हो गया।

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की जगह मिला मौका: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा की सीट रिक्त होने पर उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। 69 वर्षीय हरिवंश बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने दो कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। वे उच्च सदन के उपसभापति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

चुनावी इतिहास में पहली बार उम्मीदवार के सामने होगी ईवीएम की जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

मुंबई, एजेंसी

भारत में जब से चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ है, पहली बार है जब इसकी चुनाव के बाद जांच होने जा रही है। जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन ने ईवीएम की जांच करने का आदेश दिया है। सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान की उपस्थिति में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ईवीएम की जांच करेगा। दरअसल खान ने चांदीवली विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती दी है। विधानसभा चुनाव में खान शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ चुनाव हार गए थे।

12 फरवरी को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ और वोट चोरी का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा है कि आवेदक के लिए जब भी ईवीएम की जांच की अनुमति का आदेश दिया जाता है, उसके दो महीने के अंदर ही चुनाव आयोग को मशीनों का निरीक्षण पूरा करवना होगा।

चुनावी इतिहास में पहली बार: कोर्ट ने कहा कि भारत में इस तरह से कभी उम्मीदवार और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम की जांच नहीं की गई है। मुंबई उपनगर जिले की डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम ने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को यह 'डायग्नोस्टिक चेक' होगा।

20 ईवीएम की होगी जांच

नसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 5 फीसदी (कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट) के बर्न्ट मेमोरी, माइक्रोकंट्रोलर की जांच चुनाव परिणाम आने के बाद ईवीएम निर्माता कंपनियों और इंजीनियरों को करनी चाहिए। खान ने कहा, यह एक बड़ा फैसला है। अब तक किसी कोर्ट ने ईवीएम की जांच का आदेश नहीं दिया। यह पहले आदेश है और हम इसका स्वागत करते हैं। खान ने कहा कि कम से कम 20 ईवीएम की जांच होगी।

मेट्रो एंकर

40 दिन के अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का भयावह आंकड़ा

ईरान के 650 अटैक, जवाब में इजरायल ने किए 10,800 से अधिक हमले

वाशिंगटन, तेहरान, एजेंसी

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का एक भयावह आकड़ा सामने आया है। इजरायली सेना द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार, इस युद्ध में ईरान ने इजराइल पर 650 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं।

दरअसल, इजरायली सेना और नेताओं के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा मिलकर ईरान के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य ईरानी शासन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना, ईरान द्वारा उत्पन्न खतरों- जिसमें उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शामिल हैं- से दूरी बनाना और ईरानी लोगों के लिए शासन को उखाड़ फेंकने के लिए स्थितियां तैयार करना था।

आबादी वाले हिस्सों में गिरीं मिसाइलें

इजरायली सेना के अनुसार, लड़ाई के दौरान ईरान ने इजरायल पर लगभग 650 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इनमें से आधे से अधिक मिसाइलों में क्लस्टर बम लगे थे, जो बड़े क्षेत्रों में अंधाधुंध विस्फोट करते हैं। कम से कम 16 मिसाइलें, जिनमें सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक से लैस पारंपरिक हथियार थे, इजरायल के आबादी वाले क्षेत्रों में गिरीं, जिससे व्यापक क्षति हुई। इसके जवाब में वहीं इजराइल ने जवाब में 10,800 से अधिक हवाई हमले कर ईरानी सैन्य ढांचे को झकझोर कर रख दिया। इसके अलावा, क्लस्टर बम के वारहेड ले जाने वाली मिसाइलों के आबादी वाले क्षेत्रों में गिरने की लगभग 50 घटनाएं भी हुईं। ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले में कम से कम 20 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए। साथ ही वेस्ट बैंक में चार फिलिस्तीनी भी मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायल में 7,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

ईरान ने कब कितनी मिसाइलें दागीं?: अमेरिका-इजरायल द्वारा युद्ध के पहले दिन तेहरान पर किए हमले के तुरंत बाद ईरान ने इजरायल पर लगभग 80 मिसाइलें दागीं। इसके अगले दिन ईरान ने करीब 60 और तीसरे दिन लगभग 30 मिसाइलें दागीं। इसके बाद सीजफायर होने तक हर दिन ईरान ने औसतन 10-20 मिसाइलें दागीं। होम फ्रंट कमांड के अनुसार, ईरान द्वारा किए मिसाइल हमलों में घरों को हुए नुकसान के कारण 5,500 से अधिक इजरायली नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा*** आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564